दैनिक

लद्दाख टुडे

Title Code: LDHIN00001 | वर्ष: 03 अंक: 210 | जम्मू, कश्मीर, लेह, गुरूवार 03 सितम्बर 2026 | पृष्ठ: 8 | मूल्य 2 रुपए

संक्षिप्त...

जम्मू में एसीबी ने जूनियर असिस्टेंट को 15,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा

लद्दाख टूडे संवाददाता

जम्मू। जम्मू–कश्मीर एंटी–करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने बुधवार को एक सरकारी कर्मचारी को शादी का सर्टिफिकेट जारी करने के बदले 15,000 रूपये की रिश्वत मांगते और लेते हुए रंगे हाथों पकड़कर गिरफ़्तार किया।

आरोपी की पहचान अजय कुमार के तौर पर हुई है, जो जम्मू के गजनसू इलाके के गंगो चक के रहने वाले स्वर्गीय राम मूर्ति के बेटे हैं। वह जम्मू में असिस्टेंट कमिश्नर (जनरल) के ऑफिस में जूनियर असिस्टेंट के पद पर तैनात हैं।

एसीबी के प्रवक्ता के मुता. बिक, ब्यूरो को एक लिखित शिकायत मिली थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुमार ने स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत शादी का सर्टिफिकेट जारी करवाने में मदद करने के लिए शिकायतकर्ता से गैर–कानूनी तौर पर 20,000 रूपये की रिश्वत मांगी थी।

प्रवक्ता ने बताया कि बात. चीत के बाद, रिश्वत की मांग को घटाकर 15,000 रूपये कर ■ शेष पेज 2...

जेएंडके आरटीआई पोर्टल पर 19 महीनों में 65,000 से ज़्यादा आवे. दन और 9,000 पहली अपीलें दर्ज हुई

लद्दाख टूडे संवाददाता

जम्मू। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू–कश्मीर के ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल पर लॉन्च होने के बाद से 19 महीनों में 65,000 से ज़्यादा आरटीआई आवेदन और 9,000 पहली अपीलें मिली हैं। यह केंद्र शासित प्रदेश के नागरिकों द्वारा जानकारी पाने के लिए ऑनलाइन तरीकों के बढ़ते इस्तेमाल को दिखाता है।

ये आंकड़े जम्मू के आरटीआई एक्टिविस्ट रमन कुमार शर्मा द्वारा दायर आरटीआई आवेदन के जवाब में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (जीएडी) ने जारी किए। 27 अगस्त को जारी आधिकारिक जवाब के अनुसार, नागरिकों के लिए ऑनलाइन सूचना का अधिक. ार (आरटीआई) आवेदन दाखिल करना आसान बनाने के लिए जेएंडके आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल को आधिकारिक तौर पर 10 जनवरी, 2025 को लॉन्च किया गया था।

जीएडी ने कहा, मौजूदा रिकॉर्ड के अनुसार, पोर्टल को ■ शेष पेज 2...

------ जम्मू ---------

अधिकतम – 29°C

न्यूनतम – 22°C

------- श्रीनगर -------

अधिकतम – 23°C

न्यूनतम – 19°C

श्रीनगर में आमना-सामना : नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी ने किए अलग-अलग विरोध प्रदर्शन

लद्दाख टूडे संवाददाता

श्रीनगर। 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहली बार बड़े राजनीतिक विरोध प्रदर्शन हुए। बुधवार को सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्षी भाजपा सड़कों पर उतरे और एक–दूसरे पर जम्मू–कश्मीर के लोगों से किए गए वादे पूरे न करने का आरा. प लगाया।

नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जेएंडके का राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा पूरा न करने का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि एनसी सरकार अपने चुनावी वादे पूरे करने में नाकाम रही। राजबाग के गिंडुन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास बड़ी संख्या में एनसी के मंत्री, विधायक, नेता और कार्यकर्ता जमा हुए थे। वे राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर जवाहर नगर में बीजेपी मुख्यालय की ओर मार्च करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया।

पार्टी ने जेएंडके का राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ बीजेपी ऑफिस का श्घेरावश् करने का प्लान बनाया था। हालांकि, पुलिस और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को जवाहर नगर की ओर बढ़ने से रोक दिया। एनसी ने पुलिस पर अपने विधायकों के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया। एनसी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ष्एनसी के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ने से रोका गया। लोगों को शामिल होने से रोका गया और चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ बदसलूकी की गई। फिर भी, जब भाजपा ने सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, तो उन्हें आगे बढ़ने दिया गया। कितनी शर्म की बात है!

एनसी विधायक और मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि भाजपा ने जेएंडके का राज्य का दर्जा बहाल करने का अपना वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने पत्रकारों से कहा, ष्राज्य का दर्जा कहां है? चुनाव हुए दो साल हो गए हैं। अब हमसे किया गया वादा पूरा करने का समय आ गया है।

राज्य का दर्जा और 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा छीनी गई संवैधानिक गारंटियों को बहाल करने की मांग करते हुए सादिक ने कहा कि एनसी तब तक अपना विरोध जारी रखेगी ष्जब तक हमसे छीनी गई चीजें वापस नहीं मिल जातीं। बीजेपी ने भी उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली जेएंडके सरकार की कथित ष्विफलता॰ के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया।

एनसी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए सैकड़ों भाजपा नेता और कार्यकर्ता लाल चौक पर क्लॉक टावर के पास जमा हुए। प्रदर्शनकारियों ने जेएंडके सरकार के मुख्यालय, सिविल सचिवालय का घेराव करने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें हरि सिंह हाई स्ट्रीट के पास रोक दिया।

पार्टी कार्यकर्ताओं को संबो. धित करते हुए विधानसभा में विपक्ष ■ शेष पेज 2...

सीएम उमर अब्दुल्ला ने जेएंडके की अर्थव्यवस्था को डीकार्बोनाइज़ करने के लिए स्थानीय स्तर पर कारगर बायोमास समाधानों की मांग की

लद्दाख टूडे संवाददाता

श्रीनगर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और शैक्षणिक संस्थानों से अपील की कि वे जम्मू–कश्मीर के भरपूर बायोमास संसाधनों का इस्तेमाल करके ऐसे समाधान विकसित करें जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हों, आर्थिक रूप से फायदेमंद हों और पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ हों। इन समाधानों का मकसद जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और अर्थव्यवस्था को डीकार्बोनाइज़ करना है।

मुख्यमंत्री यहां आईईआई जेएंडके स्टेट सेंटर में द इंस्टीट्यूशन ऑफ़ इंजीनियर्स (इंडिया) (आईईआई) के केमिकल इंजीनियरिंग डिवीज़न बोर्ड और एनआईटी श्रीनगर के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के सहयोग से आयोजित श्केमिकल इंजीनियरों के 41वें राष्ट्रीय सम्मेलनश और ■ शेष पेज 2...

उमर अब्दुल्ला ने प्रदर्शनकारियों के साथ अलग-अलग बर्ताव पर सवाल उठाए बीजेपी को मदद मिली, एनसी को दबाया गया

लद्दाख टूडे संवाददाता

श्रीनगर। जम्मू–कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को पुलिस और प्रशासन पर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के विरोध प्रदर्शनों से निपटने में अलग–अलग तरीके अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जहाँ बीजेपी नेताओं को सुरक्षित रास्ता दिया गया, वहीं उनकी पार्टी के लोगों को घसीटा गया।

पत्रकारों से बात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि बुधवार को सिविल सचिवालय तक मार्च के दौरान पुलिस ने बीजेपी नेताओं की ष्मददष् की, जबकि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के साथियों को ष्बेरहमी से दबायाष् गया।

मुख्यमंत्री ने कहा, ष्आपने एक ऐसा विरोध प्रदर्शन देखा जिसकी इजाज़त नहीं दी गई। इससे आज जेएंडके के हालात का पता चलता हैरू अगर आप मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करना चाहते है, तो आपको इजाज़त है; अगर आप सचिवालय का घेराव करना चाहते हैं, तो आपको इजाज़त है; ■ शेष पेज 2...

अनंतनाग में इनोवा गाड़ी पर पत्थर गिरने से पर्यटक घायल

लद्दाख टूडे संवाददाता

अनंतनाग। बुधवार को अनंतनाग ज़िले के बुमजू मट्टन में एक भारी पत्थर के इनोवा गाड़ी से टकराने के बाद एक पर्यटक घायल हो गया।

अधिकारियों ने बताया कि यह घटना आज केपी रोड पर बुमजू मट्टन में हुई, जब बुमजू श्राइन के पास पहाड़ी से अचानक एक भारी पत्थर लुढ़ककर नीचे आया और जेके01एटी–8081 नंबर वाली इनोवा गाड़ी से टकरा गया।

इस गाड़ी को बारामूला के पट्टन के रहने वाले आरिफ दिलावर ■ शेष पेज 2...

नेपाल को 'दृढ़ संकल्प और साहस' के साथ भोटेकोशी बाढ़ संकट का सामना करना होगा: पीएम शाह

काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बुधवार को हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स को भोटेकोशी बाढ़ से हुई तबाही के बारे में जानकारी दी और कहा कि इस संकट से निपटने के लिए ष्दृढ़ संकल्प और साहसष् की ज़रूरत है।

नेपाल–तिब्बत सीमा के पास बर्फ़ और चट्टानों के गिरने या हिमस्खलन के कारण आई अचानक बाढ़ ने 26 अगस्त को उत्तरी और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, जिसमें 1,100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और 4,800 से ज़्यादा लोग लापता हो गए।

श्द काठमांडू पोस्टश की रिपोर्ट के अनुसार, शाह ने कहा, ष्संकट की इस घड़ी में, हमने इस सच्चाई को स्वीकार किया है कि देश के नेतृत्व को आंसू नहीं, बल्कि साहस, समर्थन और भरोसा देना चाहिए।ष्

शाह ने कहा कि इस आपदा ने न केवल तीन ज़िलों – रसुवा, नुवाकोट और धाडिंग – को तबाह किया है, बल्कि यह ष्पूरे देश के दिल पर एक साझा चोटष् है।

प्रधानमंत्री ने कहा, ष्हमारे पास दृढ़ संकल्प और साहस के साथ लड़ने के अलावा कोई विकल्प ■ शेष पेज 2...

जेएंडके में एनसी और बीजेपी का विरोध प्रदर्शन : राजनीतिक पार्टियों के लिए कानून अलग-अलग तरह से लागू होता है, महबूबा ने दोहरे मापदंडों की आलोचना की

लद्दाख टूडे संवाददाता

श्रीनगर। जब बीजेपी और एनसी ने यहाँ एक–दूसरे के विरोध में प्रदर्शन किए, तो पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को जम्मू–कश्मीर प्रशासन पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के विरोध प्रदर्शनों को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया।

महबूबा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ष्वही पुलिस जो पीडीपी को जनहित के मुद्दों पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए अपने कार्यालय से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देती,

उसने बीजेपी और एनसी दोनों को एक–दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने में मदद की है।

पूर्व मुख्यमंत्री लाल चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ पर टिप्पणी कर रही थीं, जो केंद्र शासित प्रदेश में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा पूरा न करने के खिलाफ रजबबाग में विरोध प्रदर्शन किया। महबू. बा ने कहा, इस खुलेआम दोहरे मापदंड का स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए; कौन इन चुनिंदा प्रतिबंधों को मंजूरी देता है और क्यों अलग–अलग राजनीतिक पार्टियों ■ शेष पेज 2...

करण सिंह ने हिमालय पर्वतमाला को बचाने के लिए हिमालयन अथॉरिटी बनाने की मांग की

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री करण सिंह ने बुधवार को हिमालयी देशों से श्हिमालयन अथॉरिटीश बनाने का सुझाव दिया ताकि इस पर्वतमाला को बचाया जा सके। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस दिशा में पहल करने का आग्रह भी किया।

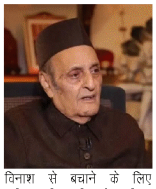

उन्होंने उत्तराखंड में चार धाम को जोड़ने वाले हाईवे को चार–लेन का बनाने को ष्निंदनीयष् बताया और कहा कि भारत सरकार को हिमालय को

विनाश से बचाने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

सिंह ने नेपाल में आपदा के कारण हुई जान–माल की हानि पर वहां के लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनका उस देश से विशेष लगाव है क्योंकि उनकी दिवंगत पत्नी वहीं की रहने वाली थीं।

सिंह ने कहा, नेपाल में हुई विनाशकारी घटनाओं से जान–माल का भारी नुकसान हुआ है। मै दुख की इस घड़ी में नेपाल के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्होंने बताया कि उनकी दिवंगत पत्नी नेपाल से थीं, इसलिए उनका उस ष्खूबसूरत देशष् और वहां के लोगों ■ शेष पेज 2...

सीएस ने जेएंडके में लगभग 40,000 करोड़ रूपये के हाईवे और टनल प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की

लद्दाख टूडे संवाददाता

श्रीनगर। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज जम्मू–कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की प्रगति की समीक्षा की। इस प्रोग्राम में नेशनल हाईवे, टनल, फ्लाईओवर, वायाडक्ट, पुल, रिंग रोड और अन्य रणनीतिक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स शामिल है, जिन्हें बीआरओ, एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल और पब्लिक वर्क्स (आरएंडबी) विभाग के ज़रिए केंद्र शासित प्रदेश में पूरा किया जा रहा है।

इस व्यापक समीक्षा में डीपीआर और सैद्धांतिक मंजूरी के चरणों में चल रहे प्रोजेक्ट्स पर भी चर्चा की गई। इन

प्रोजेक्ट्स को मंजूरी और भारत सरकार के विभिन्न प्रोग्राम्स के तहत संबंधित एजेंसियों की आगामी कार्य योजनाओं में शामिल करने के लिए ■ शेष पेज 2...

एनसी ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया, राज्य का दर्जा और संवैधानिक गारंटी बहाल करने की मांग की

लद्दाख टूडे संवाददाता

श्रीनगर। जम्मू–कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) ने बुधवार को श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से मांग की कि वह केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने और संवैधानिक गारंटी देने के अपने वादे पूरे करे।

यह विरोध मार्च बीजेपी के स्थानीय मुख्यालय की ओर निकाला गया। इसमें एनसी कार्यकर्ताओं ने जेएंडके का

राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करते हुए नारे लगाए और प्लेकार्ड दिखाए। केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद संसद और सुप्रीम कोर्ट, दोनों जगह यह मुख्य वादा किया था।

विरोध प्रदर्शन के दौरान एनसी के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने पत्रकारों से कहा, ष्हम बस दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व को याद दिलाना चाहते है कि जम्मू–कश्मीर के लोगों से किए गए वादे पूरे किए जाने चाहिए। अब वह समय आ गया है।ष्

विधायक सादिक ने कहा कि इस शांतिपूर्ण मार्च का मकसद पार्टी की मांगें केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाना था, न कि जेएंडके ■ शेष पेज 2...

राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ बने एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ट्रस्ट की बैठक में लगी मुहर, हुआ ऐलान

अयोध्या। उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को पहला सीईओ मिल गया है। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ नियुक्त किए जाने का ऐलान किया गया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। राम मंदिर के सीईओ पद के लिए 5585 आवेदन आए थे। इन आवेदनों का बहुस्तरीय मूल्यांकन दिल्ली–एनसीआर, पुणे और उड़ीसा के संबलपुर में विशेषज्ञों की टीमों ने किया।

मंगलवार को राम मंदिर ट्रस्ट को सर्च कमेटी के सचिव समीर पांड्या ने पैनल सौपा। इसके बाद बुधवार को इस पैनल पर विचार कर फाइनल निर्णय लिया गया। हालांकि, राम मंदिर के सीईओ पद पर आखिरी समय ■ शेष पेज 2...

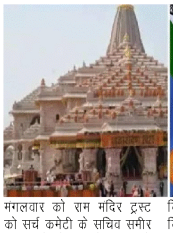

Created by Universal Document Converter

शेष पेज 1 से

जम्मू में एसीबी ने ...

दिया गया।

रिश्वत न देने की इच्छा के कारण, शिकायतकर्ता ने एंटी–करप्शन ब्यूरो से संपर्क किया और आरोपी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।

इसके बाद एसीबी ने शिकायत की गुप्त जांच की। जांच के दौरान, गैर–कानूनी रिश्वत की मांग के आरोप सही पाए गए, जिससे आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता दिखा।

जांच के बाद, एसीबी सेंट्रल जेएंडके, जम्मू पुलिस स्टेशन में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988 (2018 में संशोधित) की धारा 7 के तहत एफआईआर नंबर 11/2026 दर्ज की गई। इसके बाद ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए आरोपी को पकड़ने के लिए एक ट्रैप टीम बनाई।

ट्रैप ऑपरेशन के दौरान, एसीबी ने अजय कुमार को शिकायतकर्ता से 15,000रूपये मांगते और लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी को मौके पर ही गिरफ़्तार कर लिया गया और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में उसके पास से रिश्वत की रकम बरामद की गई।

गिरफ़्तारी के बाद, एसीबी ने आरोपी के घर की तलाशी भी ली। यह तलाशी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में ली गई। एंटी–करप्शन ब्यूरो ने कहा कि मामले की आगे की जांच चल रही है।

श्रीनगर में आमना- ...

के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि जेएंडके के लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नहीं कर रही है।

उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन चार मुद्दों पर केंद्रित था–निष्पक्ष भर्ती के बजाय नौकरियों को ष्बेचनाष् स्थानीय निकाय चुनाव न कराना; बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार; और बिजली की दरों में बढ़ोतरी। शर्मा ने अब्दुल्ला और उनकी पार्टी पर राज्य का दर्जा (स्टेटहुड) बहाल करने के मुद्दे को केवल दो. हराने और शासन पर ध्यान न देने का आरोप भी लगाया।

मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए बीजेपी नेता ने पूछा कि क्या लोगों ने उन्हें ष्राजकुमार की तरह रहने और गुलमर्ग और पहलगाम में स्कीइंग करनेष के लिए चुना था? उन्होंने अब्दुल्ला को अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र गांदरबल से इस्तीफा देने और जेएंडके को राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर नया जनादेश मांगने की चुनौती भी दी। शर्मा ने कहा, अगर आपमें थोड़ी भी आत्म–सम्मान बचा है, तो इस मुद्दे (राज्य का दर्जा) पर चुनाव लड़ें। तभी हम इसे आपका मुद्दा मानेंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा ठश्रच का है क्योंकि उसने जेएंडके के लोगों से सही समय पर इसे बहाल करने का वादा किया है। शर्मा ने कहा, ष्अगर आप (अब्दुल्ला) वास्तव में राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर विरोध करना चाहते हैं, तो गांदरबल से इस्तीफा दें। मैं आपको इस ऐतिहासिक स्थल से चुनौती देता हूं–युवराज, राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर इस्तीफा दें और नया चुनाव लड़ें।

अगर लोग आपको फिर से चुनते हैं, तो हम मान लेंगे कि राज्य का दर्जा बहाल करना आपका वास्तविक मुद्दा है। अन्यथा, हम यह निष्कर्ष निकालेंगे कि राज्य का दर्जा बहाल करना आपका मुद्दा नहीं है – यह बीजेपी का एजेंडा है। जनता को गुमराह करना बंद होना चाहिए। जेएंडके बीजेपी प्रमुख और राज्यसभा सांसद सत शर्मा ने कहा कि बीजेपी का ष्बड़ाष विरोध प्रदर्शन मुख्यमंत्री के लिए एक चेतावनी थी कि वे या तो लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरें या इस्तीफा दें।

जब बीजेपी प्रदर्शनकारियों को लाल चौक और हरि सिंह हाई स्ट्रीट की ओर इकट्ठा होने की अनुमति दी गई, तो एनसी ने प्रशासन पर भगवा पार्टी की मदद करने का आरोप लगाया। एनसी ने एक्स पर कहा, दो विरोध प्रदर्शनों की कहानी। एक, जिसे आसानी से होने दिया गया और छूट मिली। दूसरा, जिसमें सख्ती की गई और रोका गया। प्रशासन एक ही, लेकिन रवैया अलग–अलग।

गौरतलब है कि अगस्त 2019 के बाद से, अधिकारियों ने जेएंडके में ज़्यादातर राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों को सड़कों पर उतरने की इजाज़त नहीं दी है। इसी वजह से पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ़्ती ने पुलिस पर अलग–अलग राजनीतिक पार्टियों के साथ दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है।

महबूबा ने एक्स पर कहा, वही पुलिस जो पीडीपी को जनहित के मुद्दों पर शांतिपूर्ण विरोध के लिए अपने दफ़्तर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देती, उसने बीजेपी और एनसी दोनों को एक–दूसरे के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन करने में मदद की है।

उन्होंने कहा, ष्इस साफ़ दोहरे रवैये का जवाब मिलना चाहिए दृ कौन इन चुनिंदा पाबंदियों को मंजूरी देता है और क्यों अलग–अलग राजनीतिक पार्टियों के लिए कानून अलग–अलग तरह से लागू किया जा रहा है?

सीएम उमर अब्दुल्ला न ...

शबायोमासरू अर्थव्यवस्था को डीकार्बोनाइज़ करने के लिए एक टिकाऊ संसाधनश विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

इस दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन और सेमिनार में उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी, कश्मीर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. नीलोफर खान, एनआईटी श्रीनगर के निदेशक अनुराग मिश्रा, आईईआई जेएंडके स्टेट सेंटर के चेयरमैन फिरदौस अहद भट, केमिकल इंजीनियरिंग डिवीज़न बोर्ड के चेयरमैन प्रो. जी. मधु के अलावा इंजीनियर, शिक्षाविद और अन्य विशेषज्ञ शामिल हुए।

कई दशकों के अंतराल के बाद जम्मू–कश्मीर में हो रहे इस सम्मेलन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जेएंडके में आईईआई का पिछला राष्ट्रीय सम्मेलन 1989 की शुरुआत में हुआ था।

उन्होंने कहा, ष्हमारे अपने एनआईटी श्रीनगर और केमिकल इंजीनियरिंग डिवीज़न बोर्ड द्वारा आयोजित 41वें राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए आप सभी का यहां मौजूद होना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है।ष साथ ही, उन्होंने सम्मेलन का मुख्य विषय बायोमास और डीकार्बोनाइज़ेशन चुनने के लिए आयोजकों की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा और जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से पर्यावरण पर पड़ने वाले बढ़ते असर, दोनों ही नजरिए से कार्बन–आधारित ईंधन पर निर्भरता कम करने की ज़रूरत तेज़ी से बढ़ गई है।

उन्होंने कहा कि ईंधन की आपूर्ति पर हालिया दबाव ने कार्बन–आधारित ऊर्जा स्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता से जुड़ी कमज़ोरियों को उजागर किया है, जबकि जीवाश्म ईंधन के बेतहाशा इस्तेमाल के नतीजे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु–संबंधी आपदाओं के रूप में तेज़ी से दिखाई दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा, ष्हममें से जो लोग मेरी उम्र के हैं या शायद थोड़े बड़े हैं, उन्होंने अपनी आँखों से देखा है कि हमारे ग्लेशियर कैसे पीछे हट रहे हैं और सिकुड़ रहे हैं।ष उन्होंने जलवायु परिवर्तन के प्रति हिमालयी क्षेत्र के खास तौर पर संवेदनशील होने की बात कही।

सोनमर्ग के पास स्थित थाजीवास ग्लेशियर का ज़िक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लेशियर के पीछे हटने की हद को निजी अनुभव से समझा जा सकता है।

उन्होंने कहा, ष्थाजीवास ग्लेशियर देखने के लिए हमें श्रीनगर से सोनमर्ग तक बस दो घंटे का सफ़र करना पड़ता है।ष उन्होंने याद दिलाया कि कभी ग्लेशियर के निचले हिस्से तक थोड़ी दूर चलकर पहुँचा जा सकता था, जबकि आज इसके लिए काफ़ी लंबी पैदल यात्रा करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि ऐसे बदलाव जीवाश्म ईंधन के लगातार और बेरोकटोक इस्तेमाल से होने वाले पर्यावरणीय नतीजों की साफ़ याद दिलाते हैं।

हालाँकि, मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि कार्बन–आधारित अर्थव्यवस्था से दूर हटना रातों–रात ऊर्जा के एक स्रोत से दूसरे स्रोत पर स्विच करके हासिल नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा, ष्आर्थिक रूप से व्यावहारिक, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल समाधान आज की ज़रूरत हैं।ष उन्होंने ज़ोर दिया कि वैकल्पिक ऊर्जा समाधानों में बिजली के स्थापित स्रोतों के साथ आर्थिक रूप से मुकाबला करने की क्षमता होनी चाहिए।

ओमर अब्दुल्ला ने बताया कि जम्मू–कश्मीर में खेती, बागवानी, जंगलों, नगरपालिका के कचरे और बढ़ती खपत से पैदा होने वाले बायोमास के काफ़ी संसाधन मौजूद हैं।

उन्होंने कहा, ष्हम बायोमास के भंडार पर बैठे हैं, चाहे हमें यह पसंद हो या न हो।ष उन्होंने आगे कहा कि चुनौती इस संसाधन को उपयोगी ऊर्जा में बदलने के लिए असरदार तरीके विकसित करने की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू–कश्मीर अब तक शवेस्ट–टू–एनर्जीश (कचरे से ऊर्जा) के लिए एक व्यावहारिक और टिकाऊ मॉडल विकसित करने में संघर्ष कर रहा है, जबकि यहाँ ऐसे कामों को सहारा देने के लिए काफ़ी कचरा पैदा होता है।

उन्होंने देखा कि शवेस्ट–टू–एनर्जीश प्रोजेक्ट्स की आर्थिक व्यवहार्यता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, खासकर तब जब इनकी तुलना सौर और जल–विद्युत जैसे अपेक्षाकृत सस्ते स्रोतों से की जाती है।

साथ ही, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सिर्फ़ आर्थिक पहलुओं को ही कचरा प्रबंधन और ऊर्जा नीति के भविष्य का आधार नहीं बनाया जा सकता।

उन्होंने कहा, ष्हमें यह करना ही होगा।ष उन्होंने न सिर्फ़ पुराने कचरे (लेगेसी वेस्ट) की समस्या से निपटने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, बल्कि लगातार बढ़ रहे जैविक कचरे (ऑर्गेनिक वेस्ट) के निपटारे पर भी ध्यान देने को कहा, जिसे ऊर्जा में बदला जा सकता है।

उमर अब्दुल्ला ने प्रदर्शनकारियों ...

लेकिन अगर आप बीजेपी दफ़्तर के बाहर विरोध करना चाहते हैं, तो भगवान न करे, आपको इजाज़त नहीं मिलेगी, क्योंकि पुलिस वहाँ सिर्फ़ बीजेपी की इज़्ज़त बचाने के लिए है; उन्हें किसी और चीज़ की परवाह नहीं है।ष

यह बयान तब आया जब पुलिस ने एनसी प्रदर्शनकारियों को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर जवाहर नगर में बीजेपी मुख्यालय की ओर मार्च करने से रोक दिया। इससे पहले पार्टी के नेता और कार्यकर्ता राजबाग में गिंडुन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास बड़ी संख्या में जमा हुए थे।

बीजेपी ने भी जेएंडके सरकार की कथित ष्नाकामीष के खिलाफ़ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता लाल चौक पर क्लॉक टॉवर के पास जमा हुए।

प्रदर्शनकारियों ने सिविल सचिवालय – जो जेएंडके सरकार का मुख्यालय है का घेराव करने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें हरि सिंह हाई स्ट्रीट के पास रोक दिया। अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने पत्रकारों को बीजेपी नेताओं के विरोध मार्च के दौरान उनसे बातचीत करते हुए देखा।

ष्मैंने आप में से कई लोगों को उस विरोध प्रदर्शन में साथ जाते देखा। जिस आसानी से आप विपक्ष के नेता (सुनील शर्मा) का इंटरव्यू ले पाए, वह सबने देखा। आपने देखा कि कैसे बीजेपी को विरोध करने की इजाज़त मिली, लेकिन एनसी को नहीं।

ष्इसलिए, कृपया गलत तुलना न करें। एक पक्ष को मदद मिली, दूसरे को बेरहमी से दबाया गया।ष अब्दुल्ला ने दावा किया, ष्मेरे साथियों को घसीटा गया और वे घायल हो गए, और उनमें से कुछ को अस्पतालों में इलाज कराना पड़ा। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़े की सुनी शर्मा की मांग का जवाब देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि उनके पद छोड़ने का कोई कारण नहीं है।

अब्दुल्ला ने कहा, ष्मैं इस्तीफ़ा क्यों दूँ? क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि उनका इस सरकार को राज्य का दर्जा देने का कोई इरादा नहीं है? अगर ऐसा है, तो हम केंद्र से सीधे यह क्यों नहीं सुन रहे हैं? अगर वे सच में संविधान को फाड़ना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट और संसद का अनादर करना चाहते हैं और मोदी के वादे को झूठा साबित करना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा करने दें। मैं सिर्फ़ विपक्ष के नेता (एलओपी) को खुश करने के लिए इस्तीफ़ा नहीं देने वाला हूँ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जेएंडके की जनता ने उनकी पार्टी को पाँच साल के लिए जनादेश दिया है और वह उन्हें रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। (भ्रष्टाचार के) आरोपों के बारे में, क्या मेरी सरकार के पास जाँच करने का अधिकार भी है? विपक्ष के नेता हमें बताएँ कि क्या जाँच की गई थी। अगर पिछले दरवाज़े से नियुक्तियाँ हुईं, तो किस एजेंसी ने उनकी जाँच की? वे बस एक का नाम बताएँ।

उन्होंने पूछा, ष्एंटी–करप्शन ब्यूरो मेरे नियंत्रण में नहीं है। क्राइम ब्रांच मेरे नियंत्रण में नहीं है। सीआईडी मेरे नियंत्रण में नहीं है, केंद्रीय एजेंसियों की तो बात ही छोड़िए। हमें बताएँ, एफआईआर कहाँ दर्ज की गई थी? अब्दुल्ला ने बीजेपी पर बेबुनियाद आरोप लगाने का भी आरोप लगाया क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ और नहीं था। उन्होंने कहा, ष्हम उनकी गलतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं; हम उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वे ही विरोध कर रहे हैं।

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की इस टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर कि मुसलमानों का दर्जा कम नहीं किया जा सकता, मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे अमल में लाने की ज़रूरत है। हाल ही में न्यूयॉर्क में भारतीय–अमेरिकी समुदाय के सदस्यों को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा था कि अगर कोई हिंदू मानता है कि भारत में मुसलमान नहीं होने चाहिए, तो ष्वह हिंदू नहीं रहेगा।

अनंतनाग में इनोवा ...

खान चला रहे थे और इसमें छह पर्यटक पहलगाम से अनंतनाग की ओर जा रहे थे।

इस घटना में ओडिशा के गंजाम के रहने वाले 55 वर्षीय पर्यटक आर. हिमांशु प्रसाद राव गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें तुरंत इलाज के लिए जीएमसी अनंतनाग ले जाया गया।

जेएंडके में एनसी और ...

के लिए कानून अलग–अलग तरह से लागू किया जा रहा है?

पुलवामा से पीडीपी विधायक वहीद पारा ने कहा कि बीजेपी और एनसी के विरोध प्रदर्शन एक शफिक्स्ड मैचश थे। पारा ने एक्स पर पोस्ट किया, ष्आज के एनसी–बीजेपी विरोध प्रदर्शन एक तमाशा हैं। जेएंडके में प्रशासन के विफल होने और बेरोज़गारी बढ़ने के बीच, ऐसा लगता है कि वे उन लोगों के साथ शफिक्स्ड मैचश खेल रहे हैं जिन्होंने उन्हें वोट दिया था; लोग दर्शक नहीं हैं, उन्हें सब याद रहता है।

नेपाल को 'दृढ़ संकल्प ...

नहीं है, और हम लड़ रहे हैं।ष

बचाव और राहत कार्यों के बारे में बात करते हुए, पीएम शाह ने कहा कि प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्य करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया गया है, जबकि स्थानीय अधिकारियों ने लोगों को सुरक्षित इलाकों में जाने की चेतावनी दी है।

उन्होंने कहा कि सेना के हेलीकॉप्टर बचाव और लोगों को सुरक्षित निकालने के काम में लगे हुए हैं, और ज़रूरत पड़ने पर निजी हेलीकॉप्टर भी तैयार रखे गए हैं।

पीएम शाह ने कहा कि सरकार ने पीड़ितों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता को मंजूरी दे दी है और प्रभावित इलाकों को तीन महीने के लिए संकटग्रस्त घोषित कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार घायलों को मुफ़्त इलाज मुहैया करा रही है और बाढ़ से विस्थापित लोगों के लिए भोजन और रहने की व्यवस्था कर रही है।

शाह ने सदन को जानकारी दी कि स्थानीय और प्रांतीय अधिकारी बिजली, पानी की आपूर्ति और परिवहन संपर्क बहाल करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

नेपाल पुलिस के अनुसार, चितवन से 348, नवलपरासी पूर्व से 217, नवलपरासी पश्चिम से 190 और नुवाकोट से 155 शव बरामद किए गए।

इसी तरह, अब तक गोरखा से 66, धाडिंग से 59, रसुवा से 45 और तनाहु से 38 शव बरामद किए गए हैं।

सीएस ने जेएंडके म ...

तैयार किया जा रहा है।

बैठक में एसीएस, पीडब्ल्यूडी; कमिश्नर सेक्रेटरी, वन विभाग; डिविज़नल कमिश्नर, जम्मू/कश्मीर; डिप्टी कमिश्नर; चीफ इंजीनियर, प्रोजेक्ट बीकन/संपर्क; पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर; एनएचएआई और एनएचआईडीसीएल के क्षेत्रीय अधिकारी; और संबंधित विभागों व कार्यान्वयन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिनिधि शामिल हुए।

अलग–अलग हाईवे और टनल प्रोजेक्ट्स की प्रगति का विस्तार से जायज़ा लेते हुए, मुख्य सचिव ने उनकी भौतिक प्रगति और पूरा होने की संभावित तारीखों के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने जम्मू–कश्मीर के लिए इन बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के क्रांतिकारी महत्व पर ज़ोर दिया और डिविज़नल व ज़िला प्रशासन को निर्देश दिया कि वे रुकावटों को तेज़ी से दूर करने और काम की संतोषजनक गति सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करें।

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रोजेक्ट को पूरा करने में आने वाली ज़मीनी स्तर की समस्याओं की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें सक्रिय रूप से हल किया जाना चाहिए, ताकि तय समय–सीमा का पालन हो सके और इन बड़े निवेशों का लाभ जल्द से जल्द लोगों तक पहुँचे।

मुख्य सचिव ने निर्माणाधीन हाईवे पर मौजूदा सड़कों की सतह को ठीक रखने पर भी विशेष ज़ोर दिया और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि यात्री जिन हिस्सों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे गाड़ी चलाने लायक और सुरक्षित रहें। उन्होंने खराब सड़कों और अन्य कमियों पर तुरंत ध्यान देने को कहा, जिनकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है और लोगों को परेशानी होती है।

उन्होंने आगे कहा कि कनेक्टिविटी में किए जा रहे भारी निवेश से लोगों और सामान की आवाजाही तेज़, सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय होगी। साथ ही, इससे पर्यटन और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक पहुँच बेहतर होगी, जिससे उनका टिकाऊ विकास होगा और यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। शुरुआत में, पीडब्ल्यूडी के एसीएस अनिल कुमार सिंह ने जम्मू–कश्मीर में बीआरओ, एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल और पीडब्ल्यूडी के ज़रिए चलाए जा रहे बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का ब्यौरा दिया।

उन्होंने बताया कि अभी चल रहे प्रोजेक्ट्स के अलावा, एजेंसियों ने कई और सड़कों, सुरंगों और फ्लाईओवर की पहचान की है। ये प्रोजेक्ट्स इस इलाके में यात्रा को आसान बनाने और कनेक्टिविटी को ज़्यादा भरोसेमंद बनाने में गेम–चेंजर साबित हो सकते हैं, खासकर केंद्र शासित प्रदेश की मुश्किल भौगोलिक स्थिति को देखते हुए।

इस बात पर ज़ोर दिया गया कि कुल पोर्टफोलियो में 87 काम शामिल हैं, जिनकी अनुमानित लागत 1,19,736 करोड़ रुपये है। इनमें से 39,711 करोड़ रुपये की लागत वाले 44 काम अभी चल रहे हैं, जबकि 9,187 करोड़ रुपये के 11 मंजूरशुदा प्रोजेक्ट्स शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। 70,839 करोड़ रुपये की लागत वाले 32 और प्रोजेक्ट्स डीपीआर/सैद्धांतिक मंजूरी के चरण में हैं, जो कनेक्टिविटी विस्तार के अगले चरण के लिए एक बड़ी पाइपलाइन तैयार करते हैं।

करण सिंह ने हिमालय ...

से खास लगाव है।

जम्मू–कश्मीर के पूर्व गवर्नर और वरिष्ठ नेता ने कहा, ष्मुझे यह भी कहना चाहिए कि जिस घटना से यह आपदा शुरू हुई, वह तिब्बत में हुई थी। एक तरह से इस घटना ने हिमालयी क्षेत्र की नाजुकता की याद फिर से दिला दी है। यही कारण है कि मेरे जैसे हिमालय प्रेमी लगातार यह मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार को हिमालय को विनाश से बचाने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

उन्होंने जोर देकर कहा, ष्उत्तराखंड में चार धाम जैसे नाजुक इलाकों में चार–लेन वाली सड़कें बनाना निंदनीय है। इसमें बड़े पैमाने पर ब्लास्टिंग और सड़कों को चौड़ा करना शामिल है। मेरी राय में हिमालय में चार–लेन वाली सड़कों पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। ऐसा कोई कारण नहीं है कि पर्यटक और तीर्थयात्री दो–लेन वाली सड़कों पर यात्रा न कर सकें।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, ष्मैं कुछ समय से यह सुझाव दे रहा हूं कि हिमालयी देशों को एक शहिमालयन अथॉरिटीश बनानी चाहिए। इसमें पाकिस्तान, तिब्बत, भारत से लेकर बांग्लादेश और भूटान तक शामिल होंगे। तभी एक समान नीति अपनाई जा सकती है। यह उचित होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संबंध में नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर पहल करें। पुलिस ने बताया कि बुधवार को नेपाल में आई भयानक अचानक बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,127 हो गई है। बचावकर्मी हिमालयी इलाके में आई इस आपदा के एक हफ़्ते बाद भी हज़ारों लापता लोगों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं।

नेपाल पुलिस के अनुसार, चितवन से 348, नवलपरासी ईस्ट से 217, नवलपरासी वेस्ट से 190 और नुवाकोट से 155 और शव बरामद किए गए। इसी तरह, गोरखा से 66, धाडिंग से 59, रसुवा से 45 और तनाहु से 38 शव बरामद किए गए।

पुलिस ने बताया कि अब तक सुरक्षा बलों ने प्रभावित इलाकों से 6,541 लोगों को बचाया है, जबकि 4,858 लापता लोगों के लिए तलाशी अभियान जारी है। नेपाल–तिब्बत सीमा के पास बर्फ़ और चट्टानों के गिरने या हिमस्खलन से आई अचानक बाढ़ ने 26 अगस्त को उत्तरी और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया था। नेपाल में लगातार हो रही बारिश रसुवा और नुवाकोट में तलाशी और बचाव कार्यों में बाधा डाल रही है।

जेएंडके आरटीआई ...

10 जनवरी, 2025 और 26 अगस्त, 2026 के बीच 65,243 आरटीआई आवेदन मिले। साथ ही बताया कि इसी दौरान 9,033 पहली अपीलें भी मिलीं। जेएंडके पोर्टल को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 2025 में लॉन्च किया था, जबकि केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल 2013 से काम कर रहा है। जेएंडके पोर्टल पर शामिल पब्लिक अथॉरिटी, सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर (सीपीआईओ) और पहली अपीलीय अथॉरिटी की संख्या के बारे में पूछे जाने पर जीएडी ने कहा कि ज़रूरी जानकारी देने के लिए आवेदन आरटीआई एक्ट, 2005 की धारा 6(3) के तहत नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी), जेएंडके को भेजे जाते हैं।

विभाग ने कहा कि पब्लिक अथॉरिटी, सीपीआईओ या पहली अपीलीय अथॉरिटी को शामिल करने की प्रक्रिया आरटीआई एक्ट, 2005 के संबंधित प्रावधानों के अनुसार है। जीएडी ने कहा कि पब्लिक अथॉरिटी की लिस्ट और नोडल अधिकारियों की जानकारी आरटीआई पोर्टल पर उपलब्ध है। शर्मा ने कहा कि इतने कम समय में बड़ी संख्या में आवेदन मिलना यह दिखाता है कि नागरिक ऑनलाइन आरटीआई सिस्टम पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं।

उन्होंने आरटीआई पोर्टल पर और पब्लिक अथॉरिटी को शामिल करने की मांग की, जिसमें ज़िला, तहसील और ब्लॉक स्तर के अधिकारी भी शामिल हों। शर्मा ने शिक्षा विभाग का उदाहरण देते हुए कहा कि जहाँ कश्मीर और जम्मू डिवीज़न में डायरेक्टरेट लेवल पर पीआईओ आरटीआई पोर्टल पर उपलब्ध हैं, वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय वहाँ उपलब्ध नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के ज़िला कार्यालयों का भी यही हाल है। शर्मा ने कहा, जीएडी को अस्पष्ट जवाब देने या एनआईसी को सवाल भेजने के बजाय नए अधिकारियों को शामिल करने के लिए एक स्पष्ट और पारदर्शी नीति सुनिश्चित करनी चाहिए।

उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी अपील की कि वे दखल दें और इस प्रक्रिया में तेज़ी लाएँ, खासकर ज़मीनी स्तर के कार्यालयों के लिए, ताकि आम आदमी आरटीआई एक्ट से मिलने वाली पारदर्शिता का फ़ायदा उठा सके।

एनसी ने श्रीनगर में ...

में बीजेपी की स्थानीय इकाई को निशाना बनाना।

उन्होंने कहा, ष्हमें बीजेपी के स्थानीय नेतृत्व से कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय नेतृत्व को सुप्रीम कोर्ट के सामने किए गए वादों की याद दिलाना चाहते हैं। हम यहां उन वादों को पूरा कराने के लिए आए हैं।

एनसी नेता ने पार्टी की मुख्य मांगें गिनाईं, जिनमें राज्य का दर्जा बहाल करना, संवैधानिक सुरक्षा और जेएंडके के युवाओं से जुड़े आरक्षण के मुद्दे शामिल हैं। विधायक सादिक ने कहा, यह सिर्फ़ संवैधानिक गारंटी और विशेष दर्जे की बात नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों के लिए राज्य का दर्जा और आरक्षण की भी बात है। आज युवाओं के लिए कुछ किया जाना चाहिए।

उन्होंने युवाओं के लिए पदों के युक्तिकरण में देरी पर भी चिंता जताई और कहा कि रोज़गार से जुड़े मुद्दों पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। सादिक ने ज़ोर देकर कहा कि यह विरोध प्रदर्शन जेएंडके के लोगों से मिले जनादेश पर आधारित है और एनसी उस जनादेश का सम्मान और लोगों के अधिकारों की बहाली चाहती है।

उन्होंने कहा, हम यहां जम्मू–कश्मीर के लोगों द्वारा दिए गए सभी अधिकारों और जनादेश के लिए आए हैं। उस जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए। इसीलिए हम आज यहां आए हैं।

राम मंदिर ट्रस्ट के ...

तक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रिटायर्ड आईपीएस राजेश पांडेय की नियुक्ति की चर्चा थी। हालांकि, ट्रस्ट की बैठक में इस संबंध में अलग निर्णय सामने आया है।

राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से गठित सर्च कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली ने पूरी प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शी और निष्पक्ष रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि पैनल में शामिल सदस्यों का चयन मेरिट की उत्कृष्टता के आधार पर किया गया है। उन्होंने चयन समिति को लेकर कहा कि इसमें शामिल सभी लोग दूरदर्शी, भरोसेमंद और समर्पित हैं। उनमें काम करने की इच्छा है। जस्टिस कोहली ने कहा कि हम लोगों को यहां योगदान का अवसर मिला है। इसके लिए रामलला और राम मंदिर ट्रस्ट के हम आभारी हैं।

जस्टिस कोहली ने बताया कि ट्रस्ट को सौंपा गया तीन नामों का पैनल मेरिट पर आधारित है। चयन प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी रखने का प्रयास किया गया है। अब पैनल में से एक नाम राम मंदिर ट्रस्ट को तय करना है। समीर पांड्या ने पैनल ट्रस्ट को सौंपने के बाद चयन समिति में शामिल सदस्यों का धन्यवाद किया।

राम मंदिर ट्रस्ट ने 6 जुलाई को सर्च कमेटी के गठन की घोषणा की।

8 जुलाई को तीनों सदस्यों को नियुक्ति पत्र मिला।

चयन समिति की पहली बैठक 11 जुलाई को हुई। बैठक में उम्मीदवारों से आवेदन मांगने की अंतिम तिथि 18 जुलाई तय की गई। पात्र उम्मीदवारों के लिए मानदंड भी निर्धारित किए गए।14 जुलाई को समीर पांड्या को कमिटी का सचिव मनोनीत किया गया।

18 जुलाई तक कमेटी को कुल 5585 आवेदन मिले। शार्टलिस्टिंग के लिए 600 अंकों का एक गूगल फार्म बनाया गया। इसे सभी आवेदकों को भेजा गया। इनमें 3570 उम्मीदवारों ने फार्म की औपचारिकता पूरी की।

60 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवारों को ही आगे चयन के लिए रखा गया। इस तरह 108 उम्मीदवार सामने आए, जिन्हें ग्रेड ए, बी और सी में बांटा गया। 3 से 6 अगस्त अगस्त के बीच ऑनलाइन इंटरव्यू आयोजित कियागया।

ऑनलाइन इंटरव्यू के बाद 17 उम्मीदवारों का चयन कर उन्हें फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए 11 और 12 अगस्त को अयोध्या बुलाया गया। इनमें 16 प्रतिभागियों ने साक्षात्कार में हिस्सा लिया।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के आवास मणिरामदास छावनी पर बैठक का आयोजन हुआ। इसमें ट्रस्ट के पहले सीईओ की नियुक्ति को लेकर चर्चा हुई। बैठक में एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा के नाम पर सहमति बनी। ट्रस्ट की ओर से गठित सर्च कमिटी की ओर से तीन नामों का पैनल सौंपा गया था। इनमें से एक नाम को मंजूरी दी गई।

Created by Universal Document Converter

श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 4 सितंबर को अखनूर में निकलेगी भव्य शोभायात्रा

अखनूर (मोहन सिंह)। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर श्री रामलीला क्लब अखनूर की ओर से 4 सितंबर को दोपहर 3 बजे राधा–कृष्ण मंदिर से भव्य एवं विशाल शोभायात्रा निकाली जाएगी। शोभायात्रा को लेकर क्लब द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इसी संबंध में क्लब की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर आयोजन की रूपरेखा, मार्ग एवं व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई।

क्लब के पदाधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष जन्माष्टमी शोभायात्रा को पहले से अधिक भव्य और आकर्षक बनाने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। शोभायात्रा राधा–कृष्ण मंदिर से शुरू होकर अखनूर के प्रमुख बाजारों एवं मार्गों से गुजरते हुए पुनः राधा–कृष्ण मंदिर पहुंचेगी। शोभायात्रा के दौरान भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी से संबंधित भव्य झांकियां, धार्मिक प्रस्तुतियां और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहेंगे।

रामलीला क्लब की पूरी टीम पिछले लगभग एक महीने से लगातार बैठकों एवं तैयारियों में जुटी हुई है। झांकियों की तैयारी, शोभायात्रा की रूपरेखा, यातायात एवं अन्य व्यवस्थाओं के साथ–साथ विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं को आयोजन से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

क्लब ने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग कर रहे सभी सदस्यों, समाजसेवियों तथा धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों का आभार व्यक्त किया। क्लब की ओर से विशेष रूप से च्जतवद एवं पूर्व विधायक राजीव शर्मा के सहयोग की सराहना की गई। क्लब ने कहा कि राजीव शर्मा का रामलीला क्लब से वर्षों पुराना जुड़ाव रहा है और विधायक बनने के बाद भी उन्होंने क्लब के साथ अपना संबंध एवं सहयोग बनाए रखा है।

रामलीला क्लब ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, जनप्रतिनिधियों, धार्मिक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं तथा आम नागरिकों से अपील की कि वे राजनीति से ऊपर उठकर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के इस पावन आयोजन में शामिल हों और शोभायात्रा की शोभा बढ़ाएं।

जूनियर कटरा प्रीमियर लीग का आगाज, इनोवेटिव क्रिकेट अकादमी ने दर्ज की शानदार जीत

कटरा (रोहित शर्मा)। श्री माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स स्टेडियम कटड़ा में बुधवार को जूनियर कटरा प्रीमियर लीग (अंडर–16) क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि एसपी कामेश्वर पुरी ने किया। इस अवसर पर एसडीपीओ भीष्म दुबे और एसडीपीओ महेश शर्मा भी मौजूद रहे। प्रतियोगिता का आयोजन स्पोर्ट्स क्रिकेट अकादमी कटड़ा की ओर से किया जा रहा है।प्रतियोगिता में विजेता टीम को 70 हजार रुपये तथा उपविजेता टीम को 35 हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।प्रतियोगिता का पहला मुकाबला इनोवेटिव क्रिकेट अकादमी और नेक्स्ट जन क्रिकेट अकादमी के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इनोवेटिव क्रिकेट अकादमी ने निर्धारित लक्ष्य के तहत दो विकेट के नुकसान पर 134 रन बनाए। टीम की ओर से सलामी बल्लेबाज नमन कटहल ने

शानदार अर्धशतकीय पारी खेलते हुए 53 रन बनाए, जिसमें उन्होंने सात चौके लगाए। वहीं माही ने 44 गेंदों पर 47 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसमें पांच चौके और एक छक्का शामिल रहा। साहिल शर्मा ने 13 जबकि विवान चौधरी ने नौ रन का योगदान दिया।134 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नेक्स्ट जन क्रिकेट अकादमी की टीम 76 रन पर ही सिमट गई। टीम के अधिकांश बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नही कर सके। प्रभु ने 18 और गौतम ने 16 रन बनाए। इनोवेटिव क्रिकेट अकादमी के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रखा।गेंदबाजी में देवांश मल्होत्रा ने दो ओवर में महज छह रन देकर तीन विकेट हासिल किए। साहिल शर्मा ने तीन ओवर में 16 रन देकर दो विकेट, अरनव ने दो ओवर में छह रन देकर दो विकेट तथा अंगद ने दो ओवर में 12 रन देकर एक विकेट हासिल किया। नमन कटहल ने भी अपने पहले ही ओवर में एक विकेट चटकाया।शानदार बल्लेबाजी के लिए इनोवेटिव क्रिकेट अकादमी के नमन कटहल को मुख्य अतिथि एसपी कामेश्वर पुरी ने मैन ऑफ द मैच पुरस्कार प्रदान किया।इस अवसर पर एसपी कामेश्वर पुरी ने कहा कि अंडर–16 स्तर पर आयोजित होने वाली ऐसी प्रतियोगिताएं युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का बेहतर मंच प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक युवाओं को खेलों से जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि युवा जितना अधिक खेलों और सकारात्मक गतिविधियों से जुड़े रहेंगे, उतना ही वे नशे जैसी बुराइयों से दूर रहेंगे। खेलों के माध्यम से युवाओं को स्वस्थ और अनुशासित जीवन की ओर प्रेरित किया जा सकता है।गौरतलब है कि कटड़ा प्रीमियर लीग के पांचवें सीजन की शुरूआत से पहले जूनियर कटड़ा प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है।

सेई खुर्द की वर्षों से लंबित गलियों व नालियों के निर्माण का मुद्दा उठाया

जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन

जम्मू। आम आदमी पार्टी जम्मू–कश्मीर के सीनियर यूथ लीडर हरनेक सिंह रंधावा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पंचायत सई खुर्द के अंतर्गत आने वाले गांव सई कलां की लंबे समय से लंबित गलियों एवं नालियों की समस्या को लेकर संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की।

हरनेक सिंह रंधावा (हनी) ने बताया कि इन गांवों की लगभग चार गलियाँ पिछले 20–25 वर्षों से निर्माण की प्रतीक्षा में हैं। इन गलियों में न तो उचित सड़क निर्माण हुआ है और न ही नालियों की व्यवस्था की गई है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति पैदा होने के कारण लोगों के घरों में भी पानी घुसने की समस्या सामने आती है। वहीं, जिन गलियों का निर्माण हो चुका है, उनमें नालियों का काम अभी भी लंबित है। यदि समय रहते नालियों का निर्माण नहीं किया गया तो बारिश के पानी के कारण नई बनी गलियाँ भी भविष्य में क्षतिग्रस्त हो सकती हैं।

हरनेक सिंह रंधावा (हनी) ने बताया कि इस संबंध में कल ठक्‍ सुचेतगढ़ साहब से मुलाकात कर पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा की गई थी। ठक्‍ साहब ने जल्द से जल्द इन गलियों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करवाने और लोगों की

समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया।

इसके बाद आज पुनः ठक्‍ कार्यालय जाकर एसओ तथा संबंधित ग्राम सेवक से मुलाकात की गई और उन्हें इस समस्या को लेकर एक मेमोरेंडम सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों को स्थानीय लोगों की समस्याओं से अवगत करवाते हुए जल्द समाधान की मांग रखी।

केशव चोपड़ा ने नशा विरोधी जागरूकता कार्यक्रमों का किया आयोजन

जम्मू। "नशा मुक्त जम्मू–कश्मीर अभियान" के तहत युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने के अपने निरंतर प्रयासों को जारी रखते हुए, समाजसेवी एवं संवेदना सोसायटी के चेयरमैन केशव चोपड़ा ने आज राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नवाबाद तथा टाइनी टॉट्स हायर सेकेंडरी स्कूल, जम्मू में नशा विरोधी जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया।

कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को नशे के सेवन के गंभीर दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें स्वस्थ, अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। इस अवसर पर समाजसेवी एवं ओएनजीसी के पूर्व कर्मचारी दिनेश मेनन, जो अप्रैल 2026 में सेवानिवृत्त हुए है भी उपस्थित रहे।

विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए केशव चोपड़ा ने नशा मुक्त वातावरण बनाने में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को "नशे को ना और करियर को हाँ" का संदेश देते हुए युवाओं से अपनी

ऊर्जा और क्षमता को शिक्षा, खेल तथा कौशल विकास की दिशा में लगाने का आह्वान किया।

चोपड़ा ने युवाओं से नशा मुक्त जम्मू–कश्मीर अभियान के ब्रांड एंबेसडर बनकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और अन्य युवाओं को प्रेरित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की सराहना करते हुए आश्वासन दिया कि संवेदना सोसायटी इस अभियान को अपना पूर्ण सहयोग देती रहेगी।

इस अवसर पर दिनेश मेनन ने "नशा मुक्त युवा विकसित भारत" विषय पर अपनी देशव्यापी जागरूकता पदयात्रा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि युवा शक्ति नशे के खिलाफ लड़ाई में देश की सबसे मजबूत ताकत है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए सामाजिक संगठनों, शिक्षण संस्थानों, प्रशासन और समाज के सभी वर्गों के बीच आपसी सहयोग अत्यंत आवश्यक है।

करतार चंद शर्मा ने युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करने में शिक्षण संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों से पढ़ाई और सकारात्मक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया तथा संवेदना सोसायटी को भविष्य में भी पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। दीपाली हांडा ने नशे के खिलाफ लड़ाई में स्कूलों, अभिभावकों और प्रशासन की सामूहिक भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा, खेल और अपने करियर को प्राथमिकता देकर अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया।

इन कार्यक्रमों में अनन्या हांडा, पूनम गुप्ता, अंजू चोपड़ा, मनोज टंडन, अभिषेक गुप्ता, सौरव गुप्ता एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रमों का समापन इस सामूहिक संकल्प के साथ हुआ कि सभी मिलकर नशा मुक्त जम्मू–कश्मीर के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान देंगे।

जेकेएमपीसीएल की ओर से पचास किसानों का एक और जत्था प्रशिक्षण के लिए चंडीगढ़ रवाना

जम्मू। जम्मू एवं कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड की ओर से किसानों को आधुनिक डेयरी प्रबंधन, पशुपालन एवं सहकारी गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से आज तहसील मजालता, जिला उधमपुर के विभिन्न गांवों से पचास किसानों का एक दल क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान, चंडीगढ़ के लिए रवाना किया गया।

किसानों के इस दल को स्थानीय चेयरमैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान, स्थानीय प्रतिनिधि एवं जम्मू एवं कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

इस अवसर पर किसानों में विशेष उत्साह एवं खुशी देखने को मिली। किसानों ने कहा कि यह उनके लिए बेहद खुशी की बात है कि जम्मू एवं कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए चंडीगढ़ भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लगभग पचास डेयरी सहकारी समितियां कार्यरत हैं,

जिनसे लगभग पांच हजार किसान जुड़े हुए हैं। किसान इन समितियों के माध्यम से नियमित रूप से दूध की बिक्री कर अपनी आजीविका एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं।

किसानों ने जम्मू एवं कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा हाल ही में दूध के खरीद मूल्य में की गई वृद्धि तथा पशु आहार पर प्रति क्विंटल एक सौ रुपये की सब्सिडी दिए जाने की भी सराहना की। किसानों का कहना था कि इससे बढ़ती लागत के बीच उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।

इस अवसर पर स्थानीय पूर्व सरपंच ने कहा कि जब से जम्मू एवं कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा इस क्षेत्र में डेयरी सहकारी समितियों का गठन किया गया है, तब से ग्रामीण लोगों, विशेषकर किसानों को एक बेहतर एवं स्थायी रोजगार का अवसर मिला है। उन्होंने जम्मू एवं कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड से आग्रह किया कि क्षेत्र के दूर–दराज के गांवों में अधिक से अधिक डेयरी सहकारी समितियां स्थापित की जाएं और अधिक से अधिक किसानों को इस व्यवस्था से जोड़ा जाए।

इस अवसर पर जम्मू एवं कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आमिर गुप्ता ने कहा कि संस्था जम्मू–कश्मीर के किसानों के हित में दिन–रात लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय एवं डेयरी व्यवसाय को मजबूत करने के लिए हाल ही में दूध के खरीद मूल्य में वृद्धि की गई है तथा पशु आहार पर प्रति क्विंटल एक सौ रुपये की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में कुछ क्षेत्रों में पशुओं में लंपी त्वचा रोग के मामले दोबारा सामने आए हैं। किसानों के पशुधन को इस बीमारी से बचाने के लिए जम्मू एवं कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा आवश्यक दवाइयां मंगवाई गई हैं, जो अगले एक–दो दिनों में उपलब्ध होने के बाद किसानों को निःशुल्क वितरित की जाएंगी, ताकि गाय एवं भैंसों को इस बीमारी से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को सहकारी व्यवस्था से जोड़ना और उन्हें उनके गांव एवं घर के नजदीक दूध का उचित एवं बेहतर मूल्य उपलब्ध करवाना है। इसके साथ ही किसानों को पशु चिकित्सा सेवाएं, पशु आहार, चारे से संबंधित सुविधाएं तथा सरकार की विभिन्न किसान एवं पशुपालन संबंधी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए संस्था के अधिकारी एवं कर्मचारी लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं।

जागरूकता कार्यक्रम में किसानों को दी गई योजनाओं के बारे में जानकारी

आरएस पुरा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग उप जिला आरएस पुरा की तरफ से बुधवार को परंपरागत कृषि

विकास योजना के तहत पंचायत पृथ्वीपुर में एक दिवसीय किसान जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया जिसमें किसानों को सरकार की अलग–अलग योजनाओं के साथ–साथ जैविक खेती के प्रति जागरूक किया गया। एकदिवसीय जागरूक कार्यक्रम के दौरान उप जिला कृषि अधिकारी अरुण कुमार जराल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे इसके अलावा एईओ छन्नी हिम्मत नवनीत कौर, पंचायत अधिकारी परमजीत कौर के साथ–साथ बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। इस मौके पर किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक करते हुए उप जिला कृषि अधिकारी अरुण कुमार जराल ने कहा कि सरकार की तरफ से किसान वर्ग की बेहतरी के लिए अलग–अलग योजनाएं शुरू की गई है जिसका किसानों को लाभ उठाना चाहिए और किसान संबंधित कृषि कार्यालय में पहुंचकर इन योजनाओं के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने जैविक खेती पर बल देते हुए कहा कि किसान अपनी फसल में कम से कम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें और जहां तक हो सके किसान परंपरागत खेती को बढ़ावा देते हुए जैविक खेती की तरफ आगे आए है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किस समय–समय पर खेत की मिट्टी की जांच भी करवाते रहे ताकि किसानों को पता चल सके की मिट्टी में किन तत्वों की कमी है और उन्हें दूर करने के लिए कौन से उपाय करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से इस तरह के जागरूक कार्यक्रम चलाए जाएंगे और किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाई जाएगी।

यूजीसी के प्रस्तावित प्रावधानों के विरोध में कामेश्वर मंदिर में प्रेस वार्ता आयोजित

अखनूर। यूजीसी के प्रस्तावित प्रावधानों एवं जातिगत आधार पर समाज को बांटने की कोशिशों के विरोध में बुधवार को ऐतिहासिक कामेश्वर मंदिर, अखनूर में प्रेस वार्ता का

आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में ब्राह्मण सभा के प्रधान सुरेश, राजपूत सभा के प्रधान कुलवंत सिंह, सभा के प्रवक्ता राहुल लंगर सहित अन्य गणमान्य लोगों ने अपने विचार रखे।

वक्ताओं ने कहा कि हमारा सनातन धर्म महान है और सनातन परंपरा हमेशा सभी को साथ लेकर चलने की सीख देती है। सनातन धर्म की रक्षा और समाज की एकता के लिए हम सभी को मिल–बैठकर आगे बढ़ना होगा। भारतवर्ष की पहचान ही विविधता में एकता रही है, जहां अलग–अलग जाति, समुदाय और वर्ग के लोग सदियों से आपसी भाईचारे के साथ रहते आए है।

वक्ताओं ने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई भी सभी वर्गों और समुदायों ने मिल–जुलकर लड़ी थी। लेकिन आज हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि हम एक–दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे हैं, जो समाज और देश के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति है। हमें ऐसी परिस्थितियों को पैदा करने वाली हर सोच और व्यवस्था का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि समाज को जात–पात के नाम पर बांटने का कोई भी प्रयास देश की एकता और सामाजिक भाईचारे के लिए उचित नहीं है। यूजीसी द्वारा प्रस्तावित प्रावधानों को लेकर वक्ताओं ने अपना विरोध दर्ज करवाते हुए सरकार से इन पर पुनर्विचार करने तथा ऐसे प्रावधानों को लागू नहीं करने की मांग की।

आरक्षण के मुद्दे पर वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि वे जरूरतमंद लोगों के अधिकारों के खिलाफ नहीं है, लेकिन आरक्षण का लाभ वास्तविक रूप से जरूरतमंद और वंचित लोगों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने जातिगत आधार के बजाय आर्थिक एवं सामाजिक रूप से वास्तविक रूप से पिछड़े लोगों को प्राथमिकता देने की मांग रखी।

देवयानी राणा और साहिल महाजन ने भक्ति एल्बम आज मेरी माँ ने औना ए किया रिलीज़

जम्मू। देवयानी सिंह राणा और जेके यूटी भाजपा संस्कृति, कला और संस्कृति सेल की सह–संयोजक और माँ बावे वाली रिकॉर्ड्स के एमडी साहिल महाजन ने गारा राम और सामाजिक कार्यकर्ता राजीव की मौजूदगी में यह एल्बम रिलीज़ किया। यह कार्यक्रम सामाजिक कार्यकर्ता अनिका गुप्ता ने आयोजित किया था।

आज मेरी माँ ने औना ए गाना गायिका मनमीत कौर ने गाया है, इसके बोल अनिका ने लिखे हैं और संगीत राकेश आनंद ने दिया है। इसका वीडियो केके मल्होत्रा फिल्म्स ने असिस्टेंट डायरेक्टर दानिश मीर की देखरेख में तैयार किया है।

साहिल महाजन ने युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जेके भाजपा संस्कृति, कला और संस्कृति सेल की सराहना की। उन्होंने कहा कि एक सामाजिक परिवार के तौर पर हमें युवा प्रतिभाओं का

समर्थन और पोषण करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे पूरे जम्मू–कश्मीर का नाम रोशन हो। देवयानी राणा ने जम्मू–कश्मीर की युवा प्रतिभाओं की सराहना की कि उन्होंने इतना मधुर भक्ति एल्बम तैयार किया। उन्होंने कहा कि मेरी बावे वाली माँ को पूरे क्षेत्र में सभी लोग बहुत मानते हैं। उन्होंने पूरी प्रोडक्शन टीम, खासकर गायिका और माखन सिंह की एल्बम रिलीज़ करने की कोशिशों के लिए तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि आज नई सोच वाले लोगों के लिए हर जगह नए मौके खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत भूमि की सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है और कला के ये प्रेमी यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे रचनात्मक युवाओं का मन सकारात्मक सोच के साथ अपने कौशल को निखारने की ओर लगे।

देवयानी राणा ने युवा कलाकारों को उनके नए भक्ति वीडियो गाने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं और कहा कि भाजपा जम्मू–कश्मीर के हर उभरते कलाकार का समर्थन करती है। साहिल महाजन ने कहा कि यह सेल हमेशा उन लोगों का समर्थन करने के लिए तैयार है जो युवा पीढ़ी की प्रतिभा को सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और सेल हमेशा उनका हौसला बढ़ाने और ज़रूरत पड़ने पर मदद करने के लिए मौजूद है।

Created by Universal Document Converter

सम्पादकीय

जीत से आगे

किसी सरकार को परखने के लिए सौ दिन का समय बहुत कम होता है, लेकिन उसकी कार्यशैली को समझने के लिए यह काफी है। इस पैमाने पर देखें तो, पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने के बाद बीजेपी के शुरुआती महीनों ने सत्ता परिवर्तन की संभावनाओं और सीमाओं, दोनों को उजागर किया है। राजनीतिक माहौल में आया बदलाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। जो पार्टी दशकों तक बंगाल की राजनीति में हाशिए पर रही, वह अब ऐसे अधिकार के साथ शासन कर रही है जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वाम–उदारवादी राजनीतिक संस्कृति से जुड़ी संस्थाएं – जिनमें जादवपुर यूनिवर्सिटी सबसे प्रमुख है – अब एक नए वैचारिक आत्मविश्वास के प्रदर्शन का अखाड़ा बन गई हैं।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की राष्ट्रवाद की भाषा और जिसे वे डराने–धमकाने की संस्कृति कहते हैं, उसे दी गई चुनौती एक बड़ी महत्वाकांक्षा को दर्शाती हैरू न केवल सत्ता से तृणमूल कांग्रेस को हटाना, बल्कि बंगाल की राजनीतिक शब्दावली को भी बदलना। इस बदलाव की घोषणा करना इसे पूरा करने की तुलना में आसान है। बंगाल की राजनीतिक संस्कृति न तो केवल ममता बनर्जी ने बनाई थी और न ही उनके चुनावी हार के साथ यह खत्म हो जाएगी। नई वैचारिक सहमति थोपने की कोशिशों से अनावश्यक टकराव का खतरा पैदा हो सकता है, जबकि एक लोकतांत्रिक सरकार को असहमति को स्वीकार करने का आत्मविश्वास दिखाना चाहिए। फिर भी, नई सरकार को केवल प्रतीकात्मक मानकर खारिज कर देना भी उतनी ही बड़ी भूल होगी।

सीमा पर बुनियादी ढांचे के लिए लंबे समय से अटकी जमीन का हस्तांतरण और बंगाल को केंद्रीय योजनाओं से फिर से जोड़ने के प्रयास यह दिखाते हैं कि कैसे सरकार बदलने से राजनीतिक टकराव के कारण रुके हुए फैसले आगे बढ़ सकते हैं। औद्योगिक प्रोत्साहन और निवेश प्रस्ताव इस बात को स्वीकार करते हैं कि बंगाल का असली संकट आर्थिक है। यहीं असली परीक्षा है। सालों से, बंगाल औद्योगिक गिरावट, अपर्याप्त निजी निवेश और रोजगार के काबिल कई युवाओं के पलायन के नतीजों से जूझ रहा है। इन समस्याओं को योजनाओं का नाम बदलकर, आधिकारिक प्रतीकों को बदलकर या यूनिवर्सिटी परिसरों में वैचारिक लड़ाई जीतकर हल नहीं किया जा सकता है।

साथ ही, निवेश की घोषणाओं को फैक्ट्रियों से और समझौतों (मेमोरेंडम) को नौकरियों से नहीं जोड़ा जा सकता। बीजेपी को ये ढांचागत मुश्किलें विरासत में मिली हैं। यह उम्मीद करना उचित नहीं है कि वह 100 दिनों में इन्हें पूरी तरह बदल देगी। लेकिन उसके भारी चुनावी जनादेश ने राजनीतिक कमजोरी का बहाना भी खत्म कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या वह अपनी हासिल की गई सत्ता को निवेशकों के लिए जरूरी प्रशासनिक निरंतरता में बदल सकती है। राजनीतिक जीत को सफल शासन समझने में एक खास खतरा है। पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को खत्म करना नई आर्थिक व्यवस्था बनाने जैसा नहीं है। बंगाल ने ऐसी कई सरकारें देखी हैं जो राजनीति में तो ताकतवर थीं लेकिन विकास के मामले में निराशाजनक रहीं। शुरुआती महीनों से पता चलता है कि सरकार जोश से भरी, महत्वाकांक्षी और अपनी छाप छोड़ने के लिए दृढ़ है। अब तक की सबसे बड़ी कामयाबियाँ वहाँ मिली हैं जहाँ सरकार अपनी इच्छाशक्ति से तेजी से रुकावटें दूर कर सकती है। हालाँकि, उनके सबसे बड़े वादे अभी भी पूरे होने बाकी हैं। इसे अभी विफलता नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह सफलता भी नहीं है। इस सरकार की असली परख इस बात से नहीं होगी कि वह सत्ता के प्रतीकों को कितनी गहराई से बदलती है, बल्कि इस बात से होगी कि क्या बंगाल के युवा आखिरकार अपने ही राज्य में अपना भविष्य बनाने की वजह ढूंढ पाते हैं या नहीं। चुनावी जीत तो वोटिंग से मिल जाती है, लेकिन आर्थिक सुधार में बहुत ज्यादा समय लगता है।

तेजी से बदल रही है भारत की तस्वीर

प्रह्लाद सबनानी

भारत के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों, टाटा, बिरला, रिलायंस, अडानी, आदि को अपना व्यवसायिक साम्राज्य खड़ा करने में दशकों लग गए थे। इन समूहों को अपनी सम्पत्ति को 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुंचाने में लगभग 30 वर्षों का समय लगा था परंतु आज के युवावर्ग द्वारा स्थापित की जा रही कम्पनियों को अपनी सम्पत्ति को 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंचाने में केवल 1 से 3 वर्ष का समय लग रहा है। भारत में समय बहुत तेजी से बदल रहा है और भारतीय युवा आज भारत की तस्वीर बदलने को उतावले होते दिखाई दे रहे हैं। जून 2026 में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स) का व्यवसाय करने वाली सर्वम कम्पनी ने अपनी स्थापना के केवल 3 वर्ष के अंदर ही 150 करोड़ (1.5 बिलियन) अमेरिकी डॉलर की सम्पत्ति खड़ी कर ली है। इसी प्रकार, आज जेप्टो एवं मेन्सा नामक ब्राण्ड कुछ ही महीनों में व्यवसाय के उस स्तर को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे हासिल करने में पुरानी बड़ी कम्पनियों को कई दशक लग गए थे। आज के समय में टेक्नॉलोजी के क्षेत्र में स्थापित हो रही कम्पनियों की तुलना यदि इसी क्षेत्र में लगभग 20-25 वर्ष पूर्व स्थापित कम्पनियों से भी की जाय तो सम्पत्ति खड़ी करने के समय में बहुत अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। वर्ष 2000 में स्थापित कम्पनियों को यूनिकोन (100 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सम्पत्ति बनाना) बनने में लगभग 20 वर्ष से अधिक का समय लग रहा था, वहीं वर्ष 2020 में स्थापित कम्पनियों को यूनिकोन बनने में केवल एक वर्ष का समय लग रहा है। वित्तीय क्षेत्र में स्थापित की गई कम्पनियों को यूनिकोन बनने में 30 वर्ष का समय लगा है। वहीं मेन्सा ब्राण्ड जैसी कम्पनी को यूनिकोन बनने में केवल 6 माह का समय लगा है। बाजार वही है, परंतु समय तेजी से बदल रहा है। इस परिवर्तन में भारतीय युवाओं की प्रमुख भूमिका रही है। आज भारत में व्यावसायिक घरानेध्खानदान एवं अमीर लोग कहीं पीछे छूट गए हैं एवं युवा पीढ़ी तेजी से बिलिनायर की सूची में अपनी जगह बना रही है।

पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत में एक लाख से अधिक नए स्टार्ट–अप स्थापित हुए हैं। आज भारत ने अपने आप को, अमेरिका एवं चीन के बाद, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्ट–अप इको सिस्टम में स्थापित कर लिया है। भारत में आज अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से उपभोक्ता उत्पादों को बढ़ावा देने वाले स्टार्ट अप बन रहे हैं। किराना उत्पादों से संबंधित ऐप अधिक संख्या में बनाए जा रहे हैं क्योंकि यूपीआई जैसा पेमेंट गेटवे पूर्व से ही उपलब्ध है और भुगतान प्रणाली को अलग से विकसित करने की आवश्यकता ही नहीं है। साथ ही, 140 करोड़ नागरिकों का बायोमेट्रिक डाटा पहिले से ही सत्यापित है और यह उपभोक्ता उत्पादों से सम्बंधित ऐप बनाने वाले इंजीनियरों को उपलब्ध भी है। भारत में डिजिटल लाकर में 750 करोड़ से अधिक दस्तावेज जमा हो चुके हैं। सस्ता इंटरनेट डाटा उपलब्ध है एवं 90 करोड़ से अधिक भारतीय इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। इन परिस्थितियों के बीच आज 20 वर्ष के युवा एंटरप्रेन्योर को व्यवसाय स्थापना के प्रथम दिवस से ही पूरा भारत उसके उत्पाद के बाजार के रूप में उपलब्ध है। उक्त कारकों के चलते ही वर्ष 2021 में भारत में 45 नए यूनिकोन विकसित हुए थे।

भारत के पास आज दुनिया के सबसे स्मार्ट एवं कुशल इंजीनीयर तो हैं परंतु हमारे पास अपने गूगल, अपना यू ट्यूब एवं अपना फेस बुक नहीं है। क्योंकि, भारत में उच्च स्तर का तकनीकी नवाचार नहीं हो पा रहा है जिससे उच्च तकनीकी के ऐप भारत में कम बन रहे हैं। हालांकि, विकसित देशों में जो भी उच्च स्तर के तकनीकी नवाचार हो रहे हैं इनमें भारतीय इंजिनीयरों की भी महती भूमिका रहती है। इसी कारण से भारतीय इंजीनियरों की विकसित देशों में भारी मांग है। भारतीय युवाओं को दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करने के स्थान पर भारत में उच्च तकनीकी के नवाचार करने की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। अब तो विकसित देश भी यह मानने लगे हैं कि वर्तमान सदी केवल भारत की है। कई विकसित देशों सहित चीन में जनसंख्या वृद्धि दर अब ऋणात्मक हो चुकी है। साथ ही, इन देशों में वृद्ध नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पूरे विश्व में आज भारत एक युवा देश के रूप में उभर रहा है। अतः भारतीय युवाओं से न केवल भारत में आर्थिक विकास को गति देने बल्कि विश्व के अन्य कई देशों में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की अपेक्षा की जा रही है। कई देशों ने तो अपनी संसद में प्रस्ताव पास करने के उपरांत भारत सरकार से भारतीय युवाओं को इन देशों में भेजने की मांग की है।

भारतीय युवा आज न केवल भारत में तेजी से यूनिकोन विकसित कर रहा है बल्कि आज भारतीय अन्य देशों में पहुंच कर अपने व्यापार का विस्तार भी कर रहे हैं, इसी कारण से आज प्रतिवर्ष भारत से लगभग 7 लाख नागरिक विभिन्न देशों में जाकर बस रहे हैं। श्री लक्ष्मी मित्तल ने ब्रिटेन में आरसेलोर स्टील कम्पनी खरीद ली है। यह कम्पनी पूर्व में बीमार कम्पनी की श्रेणी में शामिल थी परंतु मित्तल समूह ने इसे आज विश्व की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कम्पनी बना दिया है। इसी प्रकार वर्ष 2008 में टाटा समूह ने जैग्वार एवं लैंड रोवर कम्पनी को खरीद लिया था। भारतीय मूल के नागरिक आज ब्रिटेन में जायदाद निवेशकों के क्षेत्र में सबसे बड़े निवेशक माने जा रहे हैं। यूरोप में आज भारतीय कम्पनियां सबसे अधिक राशि का निवेश करती हुई दिखाई दे रही हैं और यूरोपीयन कम्पनियों का अधिग्रहण कर रही है। अमेरिका में भी लगभग यही स्थिति है। अमेरिका में सबसे बड़ी एल्यूमिनियम उत्पादक कम्पनी को भारतीय ने खरीद लिया है। इसी प्रकार, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, अडोबी जैसी बड़ी कम्पनियों को भारतीय मूल के नागरिक ही चला रहे हैं। भारतीय मूल के ही अजय बांगा आज विश्व बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बन गए हैं। भारत में आज 15 लाख इंजिनीयर प्रतिवर्ष बन रहे हैं। विश्व के लगभग समस्त देशों को आज भारतीय युवाओं की अत्यधिक आवश्यकता है। विशेष रूप से जापान एवं यूरोपीयन देशों में प्रौढ़ नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। चीन से आज कई देश दूर भाग रहे हैं क्योंकि चीन ने विभिन्न देशों को कर्ज दे रखा है, यदि कोई देश इस कर्ज का भुगतान समय पर नहीं कर पाता है तो चीन उस देश के संसाधनों पर अपना अधिकार जताने लगता है। इससे इन देशों के साथ चीन के सम्बंध अच्छे नहीं रहे हैं। दूसरी ओर भारत में राजनैतिक स्थिरता है, जिसके चलते आज भारत के विश्व के लगभग समस्त देशों के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बंध हैं। भारत आज विश्व के कई देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते सम्पन्न कर रहा है। आज स्थिति यह निर्मित हो रही है कि भारतीय यूनिकोन अमेरिकी कम्पनियों का अधिग्रहण करने की तैयारी कर रहे हैं। भारत आज जापान, इजराईल, रूस, यूएई एवं अमेरिका जैसे देशों का रणनीतिक साझीदार है। साथ ही, भारत के सम्बंध अब चीन के साथ भी सामान्य हो रहे है। भारत आज वैश्विक दक्षिणी क्षेत्र की आवाज बन रहा है क्योंकि विश्व के कई देशों का अब चीन पर भरोसा नहीं रहा है। भारत आज जी–20 देशों के समूह का भी सदस्य है, तो जी–7 देशों के समूह एवं वैश्विक दक्षिणी क्षेत्र के बीच एक पुल का काम करता हुए भी दिखाई दे रहा है। भारत एससीओ का भी सदस्य है तो ब्रिक्स का भी सदस्य है। साथ ही, भारत क्वाड का भी सदस्य है। इस प्रकार, भारत आज विश्व के लगभग समस्त महत्वपूर्ण समूहों का सदस्य है एवं भारत के विश्व के लगभग समस्त देशों के साथ बहुत अच्छे, सौहार्दपूर्ण, व्यावसायिक एवं व्यावहारिक सम्बंध हैं। इसी कारण से ही कुशल भारतीय युवाओं की मांग आज पूरे विश्व में कई देशों द्वारा की जा रही है।

सीजेपी प्रोटेस्ट क्यों हुआ कैंसिल, सीजेआई ने ऐसा क्या कह दिया, पीएम मोदी से इसका क्या है कनेक्शन?

अभिनय आकाश

NEET-UG पेपर लीक के विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों को जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए रद्द किया, तब अदालत कक्ष में भारत के मुख्य न्यायाधीश (ब्श्रप) सूर्यकांत और श्कॉकरोच जनता पार्टीश (ब्श्रच) के बीच एक–दूसरे की सराहना देखने को मिली। यह पार्टी मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी के व्यंग्यात्मक जवाब के रूप में अस्तित्व में आई थी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने यह फैसला दिल्ली पुलिस और चार राज्य सरकारों द्वारा शीर्ष अदालत से संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का उपयोग करने की अपील के बाद सुनाया। केंद्र सरकार पर केस वापस लेने के वादे से मुकरने का आरोप लगाते हुए ब्श्रच ने 5 सितंबर को एक मार्च निकालने का ऐलान किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने के बाद इस विरोध प्रदर्शन को वापस ले लिया गया। क्यों सीजेपी ऐन मौके पर पीछे हट गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिक्चर में आ गए। बीजेपी के पीछे हटने का मतलब यह कि उन्होंने 5 सितंबर का अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया है। पर जो वजह बताई जा रही है असली बात वही है या फिर कहानी में कुछ ट्विस्ट भी है। सीजेपी का प्रोग्राम था, तारीख भी तय हो चुकी थी। 5 सितंबर की। पर फिर कहानी में यू टर्न आ गया। केंद्र सरकार पीछे हटी तो कॉकरोच जनता पार्टी वाले भी। सीजेपी वालों ने ऐलान किया 5 सितंबर को अब कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होगा। बस इसके कुछ ही देर बाद सीन में एंट्री हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उन्होंने वर्टिकल में कोई इंस्टा पर रील नहीं डाला है। बच्चों से कोई अपील भी नहीं की है। बीजेपी के अंदर से जो खबर आई है वो यह है कि प्रधानमंत्री जेन जी से संवाद करेंगे। अखबार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस पर दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (ैत्ब्ब्) जाने की संभावना है। यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि ैत्ब्ब् अपने 100 साल पूरे कर रहा है। न्यूज एजेंसी ।छप् की रिपोर्ट के मुताबिक, मोदी के कॉलेज के शताब्दी समारोह में शामिल होने और छात्रों से बातचीत करने की उम्मीद है। इस प्रस्तावित दौरे का एक अहम हिस्सा मोदी और ळमद ́ छात्रों के बीच सीधी बातचीत हो सकती है। इस सेशन से छात्रों को प्रधानमंत्री के साथ अपने विचार, उम्मीदें और चिंताएं साझा करने का मौका मिलने की संभावना है। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब ठश्रच श्जेन–श् (ळमद ́) तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। पार्टी युवाओं से जुड़ने और वोटरों की अगली पीढ़ी के साथ बातचीत को मजबूत करने के लिए एक खास रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी ने हाल ही में श्जेन जेडश (ळमद ́) तक पहुँचने के अपने कार्यक्रम के लिए एक टीम बनाई है। इसका मकसद सीनियर नेताओं और युवा प्रतिनिधियों को एक साथ लाना है। इस पहल का उद्देश्य युवा भारतीयों की उम्मीदों को समझना और बातचीत व भागीदारी के लिए और मौके बनाना है। उम्मीद है कि पार्टी युवाओं के साथ बातचीत को केवल पारंपरिक राजनीतिक कार्यक्रमों तक सीमित रखने के बजाय, सीधे जुड़ने और बातचीत करने पर ध्यान देगी। भौगोलिकसंदर्भ

बीजेपी का युवाओं तक पहुँचने का प्लान

रिपोर्ट के अनुसार, बीजेपी ने जेन जी तक पहुँचने के लिए एक खास टीम बनाई है। पार्टी नेताओं ने छोटी सभाओं, कैंपस प्रोग्राम और सीधे बातचीत के जरिए युवाओं को जोड़ने के तरीकों पर चर्चा की। अगस्त में, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने लोगों तक पहुँचने की योजना पर एक बैठक की। इसमें नेताओं ने कहा कि युवाओं को जोड़ने का काम लगातार चलना चाहिए, न कि यह सिर्फ बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों तक ही सीमित रहे। पार्टी की युवा रणनीति पर चर्चा के लिए अहम राज्यों जैसे चुनाव वाले उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के करीब 45 नेताओं को भी शामिल किया गया। पार्टी युवाओं के लिए एक अभियान की भी योजना बना रही है, जिसमें बाइक यात्रा, हैकाथॉन, मैराथन, साइकिलिंग इवेंट और इनोवेशन चौलेंज जैसी गतिविधियाँ शामिल होंगी। बीजेपी की युवा शाखा 17 सितंबर को वडनगर–वाराणसी मोटरसाइकिल यात्रा शुरू करने वाली है। पार्टी के श्सेवा पखवाड़ाश में स्कूली छात्रों, कॉलेज जाने वाले युवाओं, पोस्ट–ग्रेजुएट स्कॉलर्स और युवा इनोवेटर्स के लिए कार्यक्रम शामिल होंगे।

बीजेपी के लिए Gen Z क्यों अहम है?

पिछले महीने, छम्म्ज विवाद को लेकर युवाओं के विरोध–प्रदर्शनों ने सरकार को हिलाकर रख दिया था और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में प्रधान ने कहा कि विरोध–प्रदर्शनों के दौरान Gen Z को गुमराह करने की कोशिशें की गई थीं। इन विरोध–प्रदर्शनों में हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। छात्रों और युवा संगठनों ने पेपर लीक, छात्रों की आत्महत्या और परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों को लेकर जवाबदेही की मांग की। विरोध–प्रदर्शनों के दौरान श्कॉकरोच जनता पार्टीश (ब्श्रच) की आवाज भी प्रमुखता से सुनाई दी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि इन विरोध–प्रदर्शनों से ष्बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचा हैष और विपक्षी पार्टियों को यह समझना चाहिए कि युवा बीजेपी जैसे समूहों की ओर क्यों आकर्षित हुए। शिक्षा मंत्रालय छोड़ने के बाद, प्रधान ने अगस्त में कहा था कि NEET विरोध–प्रदर्शनों के दौरान कुछ लोगों ने जेन जी को गुमराह करने की कोशिश की थी। उन्होंने इस विवाद के चलते अपना इस्तीफा देने के फैसले का भी बचाव किया।

सीजेपी ने क्यों वापस लिया प्रोटेस्ट

5 सितंबर से फिर आंदोलन शुरू करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी ने अब अपने हाथ पीछे खींच लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई थी। इस बात पर कि स्टूडेंट प्रदर्शन को लेकर देश भर में दर्ज एफआईआर का क्या होगा? सीजीपी की शुरुआत से यह मांग थी कि एक छात्र के खिलाफ भी कारवाई नहीं होनी चाहिए। मोदी सरकार और बीजेपी के लोगों के बीच जिन कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी थी और जंतरमंतर वाला प्रोटेस्ट वापस हुआ था उनमें से एक तो यही था। तो देश की सबसे बड़ी अदालत में जब यह मामला गूंजा तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच हुए छात्र प्रदर्शनों के संबंध में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज एफआईआर पर आगे कारवाई या जांच नहीं होगी। इन सभी एफआईआर को हर मकसद के लिए बंद माना जाएगा। इसके बाद 5 सितंबर को होने वाले विरोध मार्च को वापस लेने की बात सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कह दी कि सितंबर 5 को जो हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च था इंडिया गेट से न्यू पुलिस हेड क्वार्टर्स तक वो हम लोग कॉल ऑफ कर रहे हैं क्योंकि हमारे सारे डिमांड्स सरकार ने मान लिया

तीन जजों की बेंच कर रही सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तीन जजों की बेंच कर रही है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत के अलावा बेंच में जस्टिस जॉय मौल्या बागची और जस्टिस बी मोहना भी शामिल है। भारत सरकार का पक्ष रख रहे हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। मेहता ने अदालत में कहा कि सिर्फ दिल्ली पुलिस के मामले में केंद्र सरकार ही ने नहीं बल्कि बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर दर्ज सभी एफआईआर रद्द करने की बात मान ली है। बच्चों के लिए हम कितना सोचते हैं। उनका दुख मेरा दुख है। यह अदालत में भी सरकार बता चुकी थी।

Created by Universal Document Converter

चैंबर नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने की आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक से मुलाकात

जम्मू। चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष अरुण गुप्ता के नेतृत्व में आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक प्रभाकर झा से मुलाकात की। उन्होंने आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक का पद संभालने पर उनका स्वागत किया और उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं। बैठक में डीजीएम राम स्वरूप और एजीएम गुरदीप कौर भी मौजूद थीं।

अरुण गुप्ता ने कहा कि चौबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, जम्मू व्यापार और उद्योग का एकमात्र निर्वाचित और प्रतिनिधि निकाय है। यही कारण है कि व्यापारी, उद्योगपति और आम जनता अपनी शिकायतों और समस्याओं के लिए हमारे संगठन से संपर्क करना पसंद करते है। फिलहाल हम श्द सिटिजन्स को–आप. बैक लिमिटेडश पर अचानक लगाई गई पाबंदियों पर अपनी नाराजगी जताने आए है जिसके कारण ग्राहक छह महीने की अवधि में केवल 1.25 लाख रुपये ही निकाल सकते है। इससे उस व्यापारी समुदाय में असुरक्षा की भावना पैदा हुई है जो श्द सिटिजन्स को–आप. बैंकश में अपने चालू खाते (करंट अकाउंट) चला रहे है और जिन्होंने सीसी लिमिट सुविधा का लाभ उठाया है। आरबीआई के इस कदम से उनके लेन–देन अचानक रुक गए है। अरुण गुप्ता ने आरबीआई अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे कोई सौहार्दपूर्ण समाधान निक. लें ताकि उनके व्यवसाय को नुकसान न हो।

उन्होंने आगे कहा कि बड़ी संख्या में आम ग्राहकों ने अपनी मेहनत की कमाई बैंक में चिकित्सा उपचार, शिक्षा, घरेलू खर्च, व्यावसायिक जरूरतों और बच्चों की शादी जैसी आवश्यक जरूरतों के लिए जमा की है। निकासी पर लगी पाबंदी जमाकताओं के लिए काफी कठिनाई पैदा कर रही है जो जरूरत पड़ने पर अपने ही वैध रूप से जमा किए गए फंड तक नही पहुंच पा रहे है। बैठक में उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते

हुए क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि श्द सिटिजन्स को–आपरेटिव बैंकश के कामकाज पर पाबंदियां लगाने का यह निर्णय आरबीआई के मुख्यालय द्वारा लिया गया है और हमें यह कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि बैंक की देनदारियां बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि हालांकि बैंक के मौजूदा प्रबंधन ने ईमानदारी से काम किया है जिससे एनपीए कम हुए हैं लेकिन देनदारियां बढ़ने के कारण हमें यह सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने पांच लाख रुपये से अधिक जमा किए है, उन्हें बैंक प्रबंधन से संपर्क करना चाहिए क्योंकि उनकी राशि बीमित है और उन्हें रुपये मिलेंगे। पहली बार में कुल रकम का 5.00 लाख रुपये या जो भी कम हो, वह दिया जाएगा। चौबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने जमाकताओं की बच्चों की शादी, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में जो चिंताएं जताई थीं उन पर रीजनल डायरेक्टर ने साफ कहा कि उन्हें बैंक मैनेजमेंट के जरिए आरबीआई से संपर्क करना चाहिए। आरबीआई उनके मामले को सही समाधान के लिए उच्च अधिकारियों के पास भेजेगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर छह महीने की अवधि के दौरान देनदारी कम हो जाती है तो पूरी संभावना है कि बैंक फिर से चालू हो जाएगा।

प्रतिनिधिमंडल के साथ आए अन्य पदाधिकारियों में अनिल गुप्ता (सीनियर वाइस प्रेसिडेंट), राजीव गुप्ता (जूनियर वाइस प्रेसिडेंट), मनीष गुप्ता (सेक्रेटरी जनरल) और राजेश गुप्ता (सेक्रेटरी) शामिल थे।

बचपन प्ले स्कूल में राधा-कृष्ण के रूप में सजे नन्हे-मुन्नों ने मनाई जन्माष्टमी, बाल लीलाओं की मनमोहक प्रस्तुतियों ने बांधा समां

कठुआ, 02 सितंबर। बचपन प्ले स्कूल में जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक आस्था और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नन्हे–मुन्ने बच्चे राधा–कृष्ण की मनमोहक वेशभूषा में नजर आए जिससे विद्यालय परिसर भक्तिमय हो उठा।

बच्चों ने भगवान श्रीकृष्ण के जीवन और बाल लीलाओं पर आधारित सुंदर प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और जीवन मूल्यों से भी परिचित करवाया गया।

स्कूल की निदेशक मनीषा गुप्ता ने बच्चों की उत्साहपूर्ण भागीदारी की सराहना करते हुए शिक्षकों और अभिभावकों के सहयोग के लिए आभार जताया। कार्यक्रम का आयोजन समन्वयक मोनिका शर्मा के मार्गदर्शन में किया गया। जन्माष्टमी समारोह का समापन श्रीकृष्ण के प्रेम, करुणा और धर्म के संदेश के साथ हर्षोल्लासपूर्ण माहौल में हुआ।

मोदी सरकार डीएनटी, समाज के उत्थान के लिए वचनबद्ध: केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक

केंद्र सरकार द्वारा डीएनटी, समाज का समावेश कार्यक्रम संपन्न

जम्मू। डीएनटी, अनुसूचित जाति समाज जिसमें लगभग 48 से भी ज्यादा जातियां आती हैं सभी के लिए डीएनटी, बोर्ड का गठन किया गया है जिसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों को बिजनेस व्यवसाय शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सहायता एवं कल्याणकारी योजनाएं बोर्ड के माध्यम से शुरू की गई है संपूर्ण भारतवर्ष में इसका अपना डीएनटी, बोर्ड भी बनाया गया है जिसके माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में लोगों को तमाम जन सुविधा अधिकार देने का कार्य जोरों पर किया जा रहा है डीएनटी, समाज को सम्मान देने का कार्य केंद्र में बैठी मोदी सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है समाज के उत्थान के कार्यों को लेकर देश भर में मंत्रालय के माध्यम से बोर्ड के माध्यम से कार्य युद्ध स्तर पर जारी है बोर्ड द्वारा पहली बार दिल्ली राजधानी के अंबेडकर सभागार

नई दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया जिसमें डीएनटी समाज के लोगों द्वारा अपने हाथों से बनाई गई कारीगरी वस्त्र घरेलू उपयोग की वस्तुएं उनके स्टाल लगाई गई जिन्हें लोगों ने काफी सराहा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक केंद्र राज्य मंत्री बीएल वर्मा एवं तमाम अनुसूचित जाति समाज डीएनटी, वर्ग के लोग उनके प्रमुख भारत भाई बाबू भाई पत्नी श्री प्रवीण शिवाजी राव घुगे, महंत गुरुजी राजू नाथ चंदेल, कविता राठोर, डॉ उमेश यादव पूर्व सांसद एडवोकेट धर्मवीर गुर्जर, राजेश कुमार, सी एल मीणा भाजपा एस टी, मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, राधेश्यामभारद्वाज, सुरेंद्र मनिहार नरेश चौहान सरदार राठौड़ संजय गड़िया, धर्मपाल सुल्तानपुर सुनील गाड़िया विकास कुमार देवी हिलाल बावरिया चमन सिंह हरीश महंत रोशन महाराज, सतपाल सपेरा,वातिरया, जोगिंदर सिंह बाबू सिंह दुखिया इंद्रपाल नात समाज हरि सिंह पहलवान नात समाज, सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2, जम्मू छावनी में हिंदी माह शुभारंभ समारोह आयोजित

जम्मू। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2, जम्मू छावनी में 01 सितंबर 2026 से 30 सितंबर 2026 तक हिंदी माह शुभारंभ समारोह का आयोजन किया जा रहा है। हिंदी माह का शुभारंभ विद्यालय के प्राचार्य सुनील कुमार यादव के करकमलों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया। प्रार्थना सभा में इस अवसर समस्त विद्यार्थी,शिक्षक गण,कर्मचारी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर हिंदी भाषा के महत्व, उसके व्यापक प्रयोग एवं विकास पर सारगर्भित चर्चा की गई। विद्यार्थियों को विभिन्न साहित्यकारों के साहित्यिक योगदान से परिचित कराया गया तथा हिंदी की वर्तमान स्थिति और उसके संरक्षण एवं संवर्धन पर भी विचार–विमर्श किया गया।हिंदी माह के अंतर्गत

विद्यार्थियों की रचनात्मक एवं साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें हिंदी विषय पर भाषण, स्वरचित कविता पाठ, मुंशी प्रेमचंद के जीवन एवं साहित्य पर आधारित प्रस्तुति, देशभाषा तथा साहित्यकारों के जीवन–चरित्र आदि प्रमुख रहे।

ध्यातव्य है कि संपूर्ण हिंदी माह के दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं विद्यालय के विभिन्न कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा एवं साहित्य से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इन गतिविधियों का उद्देश्य सभी को हिंदी भाषा से जोड़ना, हिंदी के प्रति रुचि एवं सम्मान की भावना विकसित करना तथा विद्यालय में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करना है।

कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्राचार्य सुनील कुमार यादव ने अपने प्रेरणादायी भाषण में हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग, प्रचार–प्रसार तथा विद्यार्थियों के दैनिक जीवन में हिंदी के प्रति सम्मान एवं अनुराग विकसित करने का संदेश दिया। सम्पूर्ण कार्यक्रम विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की उत्साहपूर्ण सहभागिता के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

लखनपुर में पशु तस्करी की कोशिश नाकाम, सात गोवंश मुक्त, कैंटर जब्त, चालक गिरफ्तार

कठुआ, 02 सितंबर। जिला कठुआ में गोवंश तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लखनपुर में एक कैंटर से सात गोवंश बरामद कर मुक्त करवाए। पुलिस ने कैंटर चालक को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिया।

जानकारी के अनुसार लखनपुर पुलिस की टीम ने नाके के दौरान पंजाब से जम्मू–कश्मीर की ओर आ रहे संदिग्ध कैंटर एचपी73ए–8133 को रोककर तलाशी ली। वाहन में सात गोवंश अमानवीय तरीके से लदे पाए गए। पुलिस ने सभी गोवंश को मुक्त करवाते हुए चालक सलमान पुत्र जुल्फकार निवासी यमुनानगर हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया। मामले में थाना लखनपुर में एफआईआर नंबर 119/2026 धारा 223 बीएनएस व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कार्रवाई एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा की देखरेख में की गई।

बिजली चोरी पर पीडीडी का शिकंजा, 305 कनेक्शन जांचे, 27 मामले अवैध मिले

कठुआ, 02 सितंबर। बिजली विभाग ने बिजली चोरी और अनियमित कनेक्शनों के खिलाफ अभियान तेज करते हुए

पिछले दो सप्ताह से नगरी से लेकर नक्कियां, नडोलियां, एरमा, सैदपुर, बडाला और हटली मोड़ तक विभिन्न क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान विभागीय टीमों ने करीब 305 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शनों की जांच की।

जांच के दौरान 27 कनेक्शन अवैध पाए गए जबकि कई अन्य मामलों में भी अनियमितताएं सामने आईं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित कनेक्शनों को मौके पर ही काट दिया गया और 29 उपभोक्ताओं पर जुर्माना भी लगाया गया। विभाग ने स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में भी यह अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा। अभियान एक्सईएन पीडीडी मोहम्मद शफी और एईई यशपाल के निर्देशन में चलाया गया जबकि निरीक्षण टीम में जगजीत सिंह, दिनेश सिंह, सुरजीत सिंह, संदीप गुप्ता और जोगिंदर लाल शामिल रहे। एक्सईएन पीडीडी मोहम्मद शफी ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे बिजली के वैध कनेक्शन लें और अपनी वास्तविक जरूरत के अनुसार स्वीकृत लोड को संशोधित करवाएं। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी मामले को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। निरीक्षण अभियान पीडीडी अधिकारियों के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है।

जम्मू में भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर नेकां का जोरदार प्रदर्शन, कई कार्यकर्ता लिए गए हिरासत में

जम्मू। जम्मू–कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन के तहत बुधवार को सत्ताधारी नेशनल कान्फ्रेंस के दर्जनों कार्यकताओं को यहां त्रिकुटा नगर में भाजपा हेडक्वार्टर की ओर मार्च करने की कोशिश करते समय हिरासत में ले लिया गया।

जम्मू के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता के नेतृत्व में नेकां कार्यकर्ता त्रिकुटा नगर बाजार में इकट्ठा हुए और घेराव करने के लिए पास के भाजपा हेडक्वार्टर की ओर बढ़ रहे थे, तभी मौके पर तैनात पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की और बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उन्हें दो गाड़ियों में बिठाकर जि"ला पुलिस लाइन्स ले जाया गया जिससे भाजपा दफ्तर का उनका प्रस्तावित घेराव नाकाम हो गया। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों में रतन लाल गुप्ता, प्रांतीय सचिव शेख बशीर अहमद और पूर्व मंत्री अजय सदोत्रा व अन्य शामिल है।

इससे पहले नेकां के एक प्रवक्ता ने कहा था कि पार्टी संसद और

सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादों के लिए जवाबदेही की मांग करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से भाजपा हेडक्वार्टर का घेराव करेगी। प्रवक्ता ने कहा कि हमारी मांगें स्पष्ट है–संवैधानिक गारंटी, राज्य का दर्जा बहाल करना, आरक्षण फाइल को मंजूरी देना और जेएंडके के लोगों के लिए न्याय। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में ऐसे संदेश लिखे प्लेकार्ड थे जिनमें कहा गया था कि भाजपा जेएंडके की आवाज उठाने में नाकाम रही, राज्य का दर्जा बहाल करो, भाजपा रोजगार पैकेज लाने में नाकाम रही और भाजपा राज्य का दर्जा मिलने में बाधा डाल रही है।

नेकां ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया और राज्य का दर्जा और संवैधानिक गारंटी बहाल करने की मांग की। प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू–कश्मीर की जनता से मिले जनादेश को श्ब्लैक चेकश नहीं माना जा सकता और लोगों से किए गए वादों को पूरा करने की मांग की। उन्होंने कहा जेएंडके की जनता का जनादेश कोई ब्लैक चेक नही है। इसका सम्मान किया जाना चाहिए इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।

सुनील डिंपल ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा और स्पेशल स्टेटस की बहाली के लिए भाजपा के खिलाफ रैली का किया नेतृत्व

जम्मू। मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट सुनील डिंपल ने सैकड़ों कार्यकताओं के साथ

जम्मू–कश्मीर डोगरा राज्य की बहाली और आर्टिकल 370 के स्पेशल स्टेटस की बहाली के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक प्रोटेस्ट रैली का नेतृत्व किया।

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए सुनील डिंपल ने आरोप लगाया कि भाजपा ने जम्मू–कश्मीर के लोगों को धोखा दिया है और अपनी नाकामी छिपाने के लिए जम्मू–कश्मीर डोगरा राज्य को बहाल नहीं कर रही है। डिंपल ने कहा कि कश्मीर में भाजपा का प्रोटेस्ट पढ़े–लिखे युवाओं में बेरोजगारी, डेवलपमेंट के कामों में पूरी तरह से करप्शन और एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, चीनी, जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों से ध्यान हटाने के लिए एक स्पान्सर्ड इवेंट था।

उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मांग की कि वे संसद में राज्य का दर्जा बहाल करने और जम्मू–कश्मीर राज्य को तुरंत बहाल करने के अपने वादों को पूरा करें। डिंपल ने जम्मू–कश्मीर राज्य का दर्जा और स्पेशल स्टेटस बहाल करने के लिए पूरे जम्मू–कश्मीर में जम्मू कश्मीर बंद का आह्वान करने की धमकी दी। डिंपल ने आरोप लगाया कि आर्टिकल 370 हटने के बाद राज्य का दर्जा न मिलने से जम्मू–कश्मीर के युवाओं और लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। डिंपल ने सभी राजनीतिक पार्टियों से जम्मू–कश्मीर राज्य की बहाली के लिए एक मंच पर आने की अपील की।

डिंपल ने कहा कि हम लद्दाख, पीओके, गिलगित, बलूचिस्तान का जम्मू–कश्मीर राज्य में एकीकरण चाहते हैं और यह भारत का अभिन्न अंग है।

भड्डू में डीसी का जनता दरबार, सड़क–पानी और स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के निर्देश

कठुआ, 02 सितंबर। ब्लॉक बिलावर के सरकारी आईटीआई कॉलेज भड्डू में बुधवार को उपायुक्त कठुआ राजेश शर्मा की अध्यक्षता में जन शिकायत शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न पंचायतों के पूर्व सरपंचों और बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, राजस्व, पर्यटन, कृषि, बागवानी और पंचायत कार्यों से जुड़ी समस्याएं एवं मांगें रखीं। इस दौरान एडीसी बिलावर विश्वजीत सिंह, पीओ आईसीडीएस मोहम्मद सैयद खान, सीपीओ रंजीत ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

उपायुक्त ने लोगों की समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों को जनहित से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविरों के माध्यम से वे समस्याएं भी प्रशासन के सामने आती है जो अक्सर जिला स्तर तक नहीं पहुंच पातीं। भड्डू–फिंतर सड़क के उन्नयन, पीएचसी भवन के पुनर्निर्माण और पेयजल संकट पर डीसी ने दिए अहम निर्देश जबकि बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की चरणबद्ध मरम्मत करवाने की जानकारी दी। पीएचसी भड्डू के नए भवन का निर्माण जल्द शुरू करने तथा तब तक अस्थायी व्यवस्था में स्वास्थ्य सेवाएं जारी रखने के निर्देश सीएमओ को दिए गए। डीसी ने भड्डू ग्राउंड के उन्नयन के लिए प्रस्ताव तैयार कर खेल विभाग को भेजने, वहीं कृषि, बागवानी और पशुपालन विभागों को किसानों के लिए जल्द मेले आयोजित कर सरकारी योजनाओं और रोजगार के अवसरों की जानकारी देने के निर्देश दिए। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और अपने गांवों को नशामुक्त बनाने में सहयोग करने की अपील भी की।

पडयारी में 9 ग्राम चिट्टा बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार

कठुआ, 02 सितंबर। नशा मुक्त जम्मू–कश्मीर अभियान के तहत कठुआ पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पडयारी क्षेत्र में करीब 9 ग्राम चिट्टे जैसा नशीला पदार्थ बरामद किया है। पुलिस ने मौके से एक कथित नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसकी मोटरसाइकिल भी जब्त की।

जानकारी के अनुसार विश्वसनीय सूचना के आधार पर पुलिस पोस्ट नगरी परोल की टीम ने पडयारी में नाका लगाकर संदिग्ध परिस्थितियों में मोटरसाइकिल सवार संजय दत्त निवासी तहसील मढ़हीन को रोका। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से करीब 9 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इस संबंध में थाना कठुआ में एफआईआर नंबर 431/2026, धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कार्रवाई एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा आईपीएस की देखरेख में की गई।

Created by Universal Document Converter

छन्नी हिम्मत हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी, परीक्षा सिर परकृविद्यार्थियों का भविष्य दांव पर: राजीव चाढ़क

"जब पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं तो 90 प्रतिशत हाजिरी की अनिवार्यता का क्या औचित्य? शिक्षा मंत्री एक विभाग नहीं संभाल पा रहे तो पद से इस्तीफा दें"

जम्मू, 2 सितंबर 2026। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, छन्नी हिम्मत, जम्मू के विद्यार्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल आज भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव चाढ़क से मिला और उन्होंने विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित होने की गंभीर समस्या से अवगत कराया।

विद्यार्थियों ने बताया कि विद्यालय में प्रिंसिपल का पद लंबे समय से रिक्त पड़ा है। इसके अलावा फिजिक्स के लेक्चरर के सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद भी खाली है। वहीं उर्दू, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लेक्चररों के पद भी रिक्त पड़े हुए हैं।

विद्यार्थियों ने विशेष रूप से बताया कि विज्ञान संकाय के तीन महत्वपूर्ण विषयकृ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजीकृके लेक्चरर उपलब्ध नहीं हैं। आगामी परीक्षाएं निकट हैं और विद्यार्थी अपनी तैयारी को लेकर चिंतित हैं। उनका कहना है कि वे अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहते और इन विषयों की पढ़ाई के लिए निजी स्तर पर सहायता लेने का प्रयास कर रहे हैं।

विद्यार्थियों ने यह भी बताया कि उन्हें 90 प्रतिशत उपस्थिति पूरी करने के लिए कहा जा रहा है, अन्यथा आगामी परीक्षा में बैठने में कठिनाई हो सकती है। चाढ़क ने कहा कि जब विद्यालय में संबंधित विषय पढ़ाने वाले शिक्षक ही उपलब्ध नहीं हैं, तो विद्यार्थियों को खाली कक्षाओं में बैठाकर उनका बहुमूल्य समय नष्ट करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अन्य विषयों के शिक्षकों से फिजिक्स, केमिस्ट्री अथवा बायोलॉजी जैसे विशिष्ट विषय पढ़ाकर विद्यार्थियों से गुणवत्तापूर्ण परीक्षा तैयारी की अपेक्षा करना भी व्यावहारिक नहीं है।

विद्यार्थियों ने बताया कि वर्तमान में सीईओ साहब प्रिंसिपल का कार्यभार देख रहे हैं, जबकि नियमित प्रिंसिपल की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव चाढ़क ने शिक्षा विभाग के आयुक्त श्री रामनिवास जी से आग्रह किया कि विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल सहित सभी रिक्त विषयवार लेक्चरर पदों को

शीघ्र भरा जाए और नियमित नियुक्तियां होने तक योग्य शिक्षकों की वैकल्पिक अथवा अस्थायी व्यवस्था की जाए, ताकि आगामी परीक्षाओं में विद्यार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

चाढ़क ने शिक्षा मंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि एक शहरी क्षेत्र के प्रमुख हायर सेकेंडरी स्कूल में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, तो इससे शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू–कश्मीर के ग्रामीण, पहाड़ी और दूरदराज क्षेत्रों में पहले से ही शिक्षकों की कमी की शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन अब शहरी क्षेत्रों में भी ऐसी स्थिति चिंताजनक है।

उन्होंने कहा कि उमर सरकार ने शिक्षा मंत्री को दो महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी है, लेकिन यदि विभागों का प्रभावी संचालन नहीं हो पा रहा और लगातार प्रशासनिक विसंगतियां सामने आ रही हैं, तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षा मंत्री अपने विभाग की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें स्वयं पद से त्यागपत्र देने पर विचार करना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो।

चाढ़क ने कहा कि जिला रामबन, डोडा और किश्तवाड़ सहित जम्मू संभाग के अनेक विद्यालयों में प्रिंसिपल और विषयवार शिक्षकों की कमी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में ऐसी कमियां विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य को सीधे प्रभावित करती हैं और सरकार को इनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए।

उन्होंने शिक्षा विभाग में सामने आ रही विभिन्न गंभीर शिकायतों का उल्लेख करते हुए कहा कि कहीं छात्राओं की सुरक्षा से जुड़े गंभीर मामले सामने आते हैं, कहीं विद्यालयों में अनुशासनहीनता की शिकायतें मिलती हैं और कहीं बच्चों की समस्याओं के समाधान के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ता है। ऐसी घटनाओं की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय करना सरकार की जिम्मेदारी है।

चाढ़क ने शिक्षा मंत्री से मांग की कि शिक्षा विभाग में चल रही विसंगतियों को तत्काल दूर किया जाए, रिक्त पदों को भरा जाए और विद्यार्थियों की शिक्षा, सुरक्षा तथा भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य को किसी भी प्रशासनिक लापरवाही अथवा देरी की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा।

2025 में सरकारी विभागों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार की 70,584 शिकायतें मिलीं; बैंक और रेलवे सबसे आगे

नई दिल्ली। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (सीवीसी) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल सरकारी संस्थाओं के खलिाफ भ्रष्टाचार की 70,500 से ज़्यादा शिकायतें मिलीं, जिनमें बैंक और रेलवे सबसे ऊपर रहे। रिपोर्ट के अनुसार, आयोग की ओर से काम करने वाले चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स (सीवीओ) को मिली 70,584 शिकायतों में से 31 दिसंबर, 2025 तक 64,905 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया।

सीवीसी की 2025 की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है, "बाकी बची 5,679 शिकायतों पर 2025 के आखिर तक काम चल रहा था, जिनमें से 2,002 शिकायतें तीन महीने से ज़्यादा समय से लंबित थीं।

सीवीओ से उम्मीद की जाती है कि वे तीन महीने के अंदर जांच पूरी कर लें। रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोग सीवीओ के पास

लंबित शिकायतों की समय-समय पर समीक्षा करता है ताकि उनका जल्द निपटारा हो सके। इसमें बताया गया है कि बैंकों के सीवीओ को सबसे ज़्यादा 9,933 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 9,520 का निपटारा किया गया और 413 लंबित थीं; इनमें से 52 शिकायतें तीन महीने से ज़्यादा समय से लंबित थीं।

रिपोर्ट के अनुसार, 31 दिसंबर, 2025 तक रेलवे से जुड़ी 9,381 शिकायतें सीवीओ को मिलीं, जिनमें से 8,754 का निपटारा किया गया और 627 लंबित थीं (10 शिकायतें तीन महीने से ज़्यादा समय से लंबित थीं)। कुल 6,531 शिकायतें हाउसिंग और शहरी मामलों से जुड़ी थीं और 4,834 शिकायतें स्थानीय निकायों के खिलाफ थीं (दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार यानी जीएनसीटीडी को छोड़कर)।

स्थानीय निकायों में दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (डीएसआईआईडीसी), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल), दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी), दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी), दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) शामिल हैं। हाल ही में सार्वजनिक की गई ईमानदारी की निगरानी करने वाली संस्था की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल मिली शिकायतों में से 4,118 शिकायतें कोयला क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों से, 3,107 वित्त क्षेत्र से, 2,804 दिल्ली सरकार के खिलाफ और 2,722 पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़ी थीं।

कुल 2,633 शिकायतें दिल्ली के खिलाफ थीं। रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस के खिलाफ ऐसी 2,139 शिकायतें थीं; सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के खिलाफ 2,139; और गृह मंत्रालय (दिल्ली पुलिस को छोड़कर) से जुड़ी 2,036 शिकायतें थीं।

रिपोर्ट में बताया गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के खिलाफ भ्रष्टाचार की 2,030 शिकायतें, श्रम मंत्रालय के खिलाफ 1,894, बीमा कंपनियों के खिलाफ 1,536 और दूरसंचार क्षेत्र से जुड़ी 1,469 शिकायतें थीं।

'राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर बीएसपी जम्मू-कश्मीर अध्यक्ष दर्शन राणा ने कई क्षेत्रों में किया सघन संपर्क अभियान'

जम्मू। बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी के स्पष्ट निर्देश पर श्री दर्शन राणा,

अध्यक्ष, बीएसपी जम्मू–कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने जल्लो चक, कालु चक, पुरमंडल और कोलादपुर सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों का सघन संपर्क अभियान एवं दौरा किया।

इस अभियान के दौरान इन क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तियों से व्यक्तिगत संपर्क किया गया। बहन जी का संदेश प्रभावी ढंग से पहुँचाया गया और लोगों से विस्तृत चर्चा की गई। उन्हें बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने तथा बहुजन आंदोलन को मजबूत करने के लिए दृढ़ अपील की गई।

बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का ऐतिहासिक सपना कि "राजनीतिक सत्ता वह मास्टर चाबी है जो सभी ताले खोल देती है" अवश्य पूरा होना चाहिए। मान्यवर कांशी राम जी ने सही कहा था कि जिनके पास राजनीतिक सत्ता होती है, उनके साथ कोई अन्याय नहीं किया जा सकता।

दौरे के दौरान मिले सभी व्यक्तियों ने बहुजन समाज पार्टी को अपना पूर्ण समर्थन देने का दृढ़ आश्वासन दिया तथा पार्टी के विस्तार एवं जमीनी स्तर पर मजबूती के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया। इस संपर्क अभियान में सत्पाल बावोरिया, चमन लाल, दीप राज और रजिंदर लाल पार्टी अध्यक्ष के साथ उपस्थित रहे।

कारगिल में पासपोर्ट से जुड़ी सेवाओं को आसानी से पाने के लिए पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खुला

कारगिल/जम्मू। अधिकारियों ने बताया कि लद्दाख के कारगिल में बुधवार को पोस्ट

ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) का उद्घाटन किया गया, ताकि वहां के लोगों को पासपोर्ट से जुड़ी सेवाएं आसानी से मिल सकें।

विदेश और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लद्दाख के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना और सांसद मोहम्मद हनीफा जान की मौजूदगी में इसका उद्घाटन किया।

उन्होंने बताया कि डाक विभाग और पासपोर्ट सेवा के बीच हुए समझौते (एमओयू) के तहत शुरू किए गए इस पीओपीएसके का मकसद लद्दाख के दूर-दराज और भौगोलिक रूप से मुश्किल इलाकों में रहने वाले लोगों तक नागरिकों के लिए पासपोर्ट सेवाएं आसानी से पहुंचाना है।

इस सुविधा से आवेदकों को पासपोर्ट से जुड़ी सेवाएं अपने घर के पास ही मिल सकेंगी। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें पहले ऐसी सेवाओं के लिए श्रीनगर या दूसरे दूर के केंद्रों पर जाना पड़ता था।

उन्होंने कहा कि पीओपीएसके का खुलना इस बात को दिखाता है कि जरूरी नागरिक सेवाएं पहुंचाने के लिए, खासकर दूर-दराज और कम सुविधा वाले इलाकों में, डाक विभाग के बड़े नेटवर्क का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है।

उम्मीद है कि इस पहल से पासपोर्ट सेवाएं ज़्यादा आसानी से उपलब्ध होंगी, बेहतर होंगी और लोगों के लिए सुविधाजनक बनेंगी।

उन्होंने बताया कि लद्दाख पोस्टल डिवीजन ने इस केंद्र को खोलकर अपने जन-सेवा ढांचे में एक और उपलब्धि हासिल की है। यह पहल लद्दाख पोस्टल डिवीजन के पोस्ट ऑफिस सुपरिंटेंडेंट अरविंद खेर के नेतृत्व में शुरू की गई थी।

जेएंडके विधानसभा ने ऑटम सेशन से पहले एनईवीए की तैयारियों का लिया जायज़ा

श्रीनगर। जम्मू–कश्मीर विधानसभा में बुधवार को एक हाई-लेवल मीटिंग हुई, जिसमें आने वाले ऑटम सेशन से पहले

नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (एनईवीए) को लागू करने की तैयारियों का जायजा लिया गया।

इस मीटिंग की अध्यक्षता कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग के सचिव अचल सेठी ने की, जिसमें जम्मू–कश्मीर विधानसभा के सचिव मनोज कुमार पंडित भी शामिल हुए।

बातचीत मुख्य रूप से एनईवीए प्लेटफॉर्म को असरदार ढंग से शुरू करने और चलाने के लिए जरूरी इंतज़ामों पर केंद्रित थी। इस प्लेटफॉर्म का मकसद विधायी कामकाज को डिजिटल और पेपरलेस बनाना है।

अधिकारियों ने तकनीकी तैयारियों, विधायी कामकाज की डिजिटल प्रोसेसिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन और संबंधित विभागों के बीच तालमेल की स्थिति का जायजा लिया। मीटिंग में इस बात पर भी जोर दिया गया कि ऑटम सेशन शुरू होने से पहले सभी जरूरी तकनीकी और प्रशासनिक इंतजाम पूरे कर लिए जाएं।

एनईवीए सिस्टम को विधायी दस्तावेज़ों और कामकाज को डिजिटल रूप से संभालने के लिए बनाया गया है, ताकि कागजी काम पर निर्भरता कम हो और विधानसभा, विधायकों और सरकारी विभागों के बीच बातचीत आसान हो सके। अधिकारियों ने सभी स्टेकहोल्डर्स के बीच करीबी तालमेल की जरूरत पर जोर दिया ताकि आने वाले सेशन के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए विधायी कामकाज आसानी से हो सके।

जेएंडके विधानसभा के एनईवीए पोर्टल पर ऑटम सेशन 2026 और उससे जुड़ी सूचनाएं भी लिस्ट की गई हैं, जिससे पता चलता है कि सेशन और उसकी डिजिटल कार्यवाही की तैयारियां चल रही हैं। मीटिंग का समापन संबंधित अधिकारियों को करीबी तालमेल बनाए रखने और पेपरलेस विधानसभा के सुचारू कामकाज के लिए लंबित तकनीकी और प्रक्रियात्मक जरूरतों को समय पर पूरा करने के निर्देशों के साथ हुआ।

विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने सीएम अब्दुल्ला को दी चुनौती

कहा–वे गांदरबल से इस्तीफ़ा दें और राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर नया जनादेश लें

श्रीनगर। बुधवार को बीजेपी ने जम्मू–कश्मीर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को चुनौती दी कि वे अपनी गांदरबल सीट से इस्तीफ़ा दें और राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर नया जनादेश लें।

हाथों में पोस्टर लिए बीजेपी नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता लाल चौक पर क्लॉक टावर के पास जमा हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के खिलाफ नारे लगाए।

शर्मा ने कहा कि लाल चौक से बीजेपी कार्यकर्ता अपने विरोध प्रदर्शन के तहत सिविल सचिवालय की ओर मार्च करेंगे।

पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि जेएंडके के लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।

"आम और गरीब लोगों के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया है। पूरे जेएंडके में पानी का संकट है, फिर भी कोई फिटर या एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर नज़र नहीं आता, मंत्री की तो बात ही छोड़िए।

शर्मा ने कहा, "अस्पतालों में जाइए तो वहां न डॉक्टर है, न मेडिकल स्टाफ, और न ही गरीबों की देखभाल करने वाला कोई है। स्कूलों में जाइए तो न शिक्षक है, न मास्टर है, और न ही हेडमास्टर है।"

अब्दुल्ला की आलोचना करते हुए शर्मा ने पूछा कि क्या लोगों ने उन्हें "शाहजादा की तरह रहने और गुलमर्ग व पहलगाम में स्कीइंग करने के लिए" चुना था?

उन्होंने अब्दुल्ला को चुनौती दी कि वे अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र गांदरबल से इस्तीफ़ा दें और जेएंडके को राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर नया जनादेश लें।

एम्वे ने आयुर्वेद में विस्तार के साथ 'विकसित भारत' के लक्ष्य को दिया समर्थन

न्यूट्रिलाइट आयुर्वेद के तहत नौ नए उत्पाद दो साल में 100 करोड़ रुपये के कारोबार का लक्ष्य

जिम्मेदार सोर्सिंग और स्थानीय किसानों के सहयोग से लेकर तमिलनाडु स्थित फैक्ट्री में उत्पादन तक, 'मेक इन इंडिया' को आगे बढ़ाती पहल

जम्मू, सितम्बर 02। भारत की राष्ट्र-निर्माण की प्राथमिकताओं और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जुड़ते हुए, हेल्थ और वेलनेस कंपनी एम्वे इंडिया ने आज न्यूट्रिलाइट आयुर्वेद के साथ आयुर्वेद में एक अहम रणनीतिक कदम की घोषणा की। यह कदम ऐसे समय आया है जब उपभोक्ता पेड़-पौधों पर आधारित उत्पादों की ओर बढ़ रहे हैं, बीमारी से पहले बचाव को अहमियत दे रहे हैं, और सरकार आयुष को लगातार मजबूत कर रही है। कंपनी ने इस श्रेणी में नौ नए आयुर्वेदिक उत्पाद उतारे हैं और अगले दो साल में इसे 100 करोड़ रुपये का कारोबार बनाने का लक्ष्य रखा है। इनमें इस्तेमाल होने वाली जड़ी-बूटियां ऑर्गेनिक खेती करने वाले न्यूट्रीसर्ट प्रमाणित खेतों से जिम्मेदारी के साथ ली जाती हैं और उत्पाद तमिलनाडु स्थित एम्वे की अत्याधुनिक फैक्ट्री में तैयार होते हैं।

यह कदम एम्वे इंडिया के उत्पादों की श्रृंखला बढ़ाने भर का नहीं है। यह भारत में आयुर्वेद से जुड़ी पूरी आर्थिक श्रृंखला को मजबूत करने का मौका है, जिसमें स्थानीय खेती, मैन्युफैक्चरिंग, वैज्ञानिक शोध, इनोवेशन और रोजगार शामिल हैं। न्यूट्रिलाइट के 90 साल से अधिक के बॉटनिकल साइंस के अनुभव और भारत में एक दशक की विनिर्माण क्षमता के साथ कंपनी आयुर्वेद के सदियों पुराने ज्ञान को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर परख रही है। वेलनेस की यह सोच भारत में, भारत के लिए तैयार हुई है और इसमें देश की पारंपरिक वेलनेस परंपरा को दुनिया तक ले जाने की क्षमता है।

इस लॉन्च के मौके पर एम्वे इंडिया के प्रबंध निदेशक श्री रजनीश चोपड़ा ने कहा, "भारत में पारंपरिक स्वास्थ्य और वेलनेस का पूरा परिदृश्य बदल रहा है। सरकार का जोर आयुष को मजबूत करने और आयुर्वेद को देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का अहम हिस्सा बनाने पर है। इससे देश के भीतर आयुर्वेद को मजबूत आधार मिला है और दुनिया में इसकी पहचान भी बढ़ी है। जैसे-जैसे भारत आयुर्वेद से जुड़े इनोवेशन और विनिर्माण में अपनी क्षमता बढ़ाएगा, यह बढ़ता इकोसिस्टम नए आर्थिक अवसर पैदा कर सकता है, भारत की क्षमताओं को मजबूत कर सकता है और पारंपरिक वेलनेस के वैश्विक केंद्र के रूप में देश को उभरने में मदद कर सकता है। यह दिशा एम्वे इंडिया के विकास के अगले चरण और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य, दोनों से मेल खाती है। आयुर्वेद की अपार क्षमता पर भरोसा जताते हुए हमने अगले दो साल में न्यूट्रिलाइट आयुर्वेद को 100 करोड़ रुपये का कारोबार बनाने का लक्ष्य रखा है। पोषण की गहरी वैज्ञानिक समझ, न्यूट्रिलाइट के 90 साल से अधिक के बॉटनिकल साइंस के अनुभव और प्रमाणों के साथ एम्वे इंडिया आयुर्वेद के लिए भारत के रणनीतिक रोडमैप में योगदान देने की खास स्थिति में है।"

उन्होंने आगे कहा, "आयुर्वेद अब लोगों की रोजमर्रा की सेहत का

हिस्सा बन रहा है। लेकिन उपभोक्ता उसमें भी वही पारदर्शिता, वही एकसमान गुणवत्ता और वही वैज्ञानिक प्रमाण चाहते हैं, जिसकी उम्मीद वे आधुनिक वेलनेस उत्पादों से करते हैं। न्यूट्रिलाइट में हमारा मानना है कि भरोसा ही हर पेशकश की बुनियाद है। न्यूट्रिलाइट आयुर्वेद के लिए हर जड़ी-बूटी की अपनी कहानी है और हम उसकी सच्चाई सुनिश्चित करते हैं, यह सिर्फ एक वादा नहीं है। यह उपभोक्ता तक पहुंचने वाली हर जड़ी-बूटी की गुणवत्ता और ट्रेसेबिलिटी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, ताकि लोग पूरे भरोसे के साथ आयुर्वेद अपना सकें।"

पहले चरण में तीन आयुर्वेदिक फॉर्मूलेशन बाजार में आ रहे हैं। कालमेघ लिवर के बेहतर कामकाज में मदद करता है। शिग्रु (मोरिंगा) शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा होने और सूजन को कम करने में मदद करता है। वृक्षाम्ल (गार्सिनिया) मेटाबॉलिज्म बेहतर बनाने और पेट भरे रहने का अहसास बनाए रखने में मदद करता है।

उपभोक्ता अब इलाज से ज्यादा बचाव पर ध्यान दे रहे हैं। वे यह भी जानना चाहते हैं कि उत्पाद में इस्तेमाल हुई सामग्री कहां से आई है, कितनी असरदार है और कितनी प्रामाणिक है। इस पूरी श्रृंखला के केंद्र में न्यूट्रिलाइट है, जो पिछले 90 साल से अधिक समय से प्रकृति और विज्ञान का बेहतरीन मेल लाता आया है। न्यूट्रिलाइट आयुर्वेद में यही विरासत आयुर्वेद के परखे हुए ज्ञान से मिलती है और इस श्रेणी की उस बड़ी कमी को पूरा करती है, जो भरोसे, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को लेकर है।

यह पूरी श्रृंखला ऑर्गेनिक खेती करने वाले न्यूट्रीसर्ट प्रमाणित खेतों से जिम्मेदारी के साथ ली गई प्रामाणिक आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों पर टिकी है, जो टिकाऊ खेती और जिम्मेदार सोर्सिंग के प्रति न्यूट्रिलाइट की लंबी प्रतिबद्धता दिखाती है। हर फॉर्मूलेशन न्यूट्रिलाइट की आरएंडडी विशेषज्ञता और वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित है तथा कड़ी गुणवत्ता प्रक्रियाओं से गुजरता है। इनमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एक्टिव टेस्टिंग और सीड-टू-सप्लीमेंट ट्रेसेबिलिटी शामिल है, जो प्रामाणिकता, एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। इसके अलावा दूषित तत्वों, भारी धातुओं, माइक्रोबायोलॉजिकल सुरक्षा और प्रमुख मार्कर कंपाउंड्स की एकरूपता की जांच कई चरणों में होती है। यह जांच बुनियादी नियामक जरूरतों से आगे जाकर वही गुणवत्ता, प्रामाणिकता और एकरूपता देती है, जिसकी उम्मीद उपभोक्ता न्यूट्रिलाइट से करते हैं।

इस श्रृंखला में आयुष पंजीकृत फॉर्मूलेशन भी शामिल हैं। इससे लागू नियामक ढांचे के मुताबिक उत्पाद तैयार करने की एम्वे इंडिया की प्रतिबद्धता मजबूत होती है और उपभोक्ता को अपनी पसंद की गुणवत्ता तथा प्रामाणिकता पर ज्यादा भरोसा मिलता है।

यह लॉन्च कंपनी की ओर से इसी श्रेणी में पहले पेश किए गए न्यूट्रिलाइट च्यवनप्राश के अनुभव पर आगे बढ़ता है। न्यूट्रिलाइट आयुर्वेद की नींव इस सोच पर है कि सदियों पुराने आयुर्वेदिक फॉर्मूलेशन को उसी सटीक, विज्ञान आधारित तरीके से परखा जाए जो दशकों से न्यूट्रिलाइट की पहचान रहा है। कालमेघ 449 रुपये, शिग्रु 661 रुपये और वृक्षाम्ल 449 रुपये के एमआरपी पर 6 सितंबर 2026 से एम्वे के सभी अधिकृत चैनलों, एम्वे बिजनेस ओनर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स, एम्वे स्टोर्स और ऐप पर उपलब्ध होंगे।

Created by Universal Document Converter

वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने वाहन कलपुर्जा उद्योग से ग्लोबल स्तर पर काम करने का आह्वान किया

बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ हैय वाहन क्षेत्र में जबरदस्त दोहरे अंकों की ग्रोथ दर्ज की गईः श्री गोयल

नई दिल्ली। नई दिल्ली में ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एसीएमए) के 66वें सालाना अधिवेशन को संबोधित करते हुए, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज वाहन कलपुर्जा उद्योग से कहा कि वे स्थानीय कारोबारों को वैश्विक कारोबारों में बदलें, विकसित देशों में विनिर्माण का दायरा बढ़ाएं, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाएं और मूल्य श्रृंखला में ऊपर की ओर बढ़ें, क्योंकि भारत वैश्विक बाजार के साथ अपने जुड़ाव को गहरा करना चाहता है।

श्री गोयल ने कहा कि उद्योग का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जो आयात और निर्यात के बीच बराबर बंटा हुआ था। उन्होंने कहा कि कारोबार तब फलता–फूलता है जब वह वैश्विक स्तर पर सोचता है और किसी देश की आर्थिक प्रगति में आयात भी अहम भूमिका निभा सकते हैं, साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि इसे आयात बढ़ाने के लिए बढ़ावा देने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि आयात और निर्यात के बीच के अंतर को बढ़ाने का वादा किया गया था, लेकिन यह काम अभी शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने आने वाले वर्षों में एसीएमए और इसके सदस्यों की ओर से बड़े पैमाने पर अंत. रराष्ट्रीय निवेश और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने का आह्वान किया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस उद्योग को पिछले कुछ वर्षों में सहयोग से फायदा हुआ है और इसने भारत में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता वाले सामान बनाने की क्षमता हासिल कर ली है। उन्होंने उद्योग से कहा कि अब वे दुनिया भर में अपने विनिर्माण का दायरा बढ़ाएं और विकसित देशों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं।

श्री गोयल ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले चार–पांच वर्षों में पूरे किए गए नौ व्यापार समझौतों के जरिए भारत की बढ़ती बाजार पहुंच पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन समझौतों में 38 विकसित देश शामिल हैं, जिनकी कुल जीडीपी 60 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले हुए मुक्त व्यापार समझौतों की कुल जीडीपी आज के मूल्य के हिसाब से 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जबकि मौजूदा सरकार के तहत पिछले साढ़े चार वर्षों में हुए नौ समझौतों से 60 ट्रिलियन अमे. रिकी डॉलर की जीडीपी वाली अर्थव्यवस्थाओं तक दोनों तरफ से बाजार की पहुंच मिलती है।

उन्होंने कहा कि इन समझौतों में ज्यादा जीडीपी और ज्यादा प्रति व्यक्ति जीडीपी वाले समृद्ध देश शामिल हैं, जिनसे भारतीय उद्योग को कम प्रतिस्पर्धा और ज्यादा पूरकता मिलती है। श्री गोयल ने भारत के मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत में एसीएमए की भूमिका को भी माना। उन्होंने कहा कि इस संगठन ने लगातार भारतीय वाहन कलपुर्जा क्षेत्र के लिए जीरो–ड्यूटी पहुंच की मांग की है और साथ ही भारतीय बाजार को भी पारस्परिक रूप से खोलने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि यह उद्योग दुनिया की बेहतरीन कंपनियों का मुकाबला करने में सक्षम है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए तैयार है।

सत्र की थीम दृ "लचीलेपन से आगेरू अनिश्चितताओं को संभालना, नए रास्ते बनाना और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला" दृ का उल्लेख करते हुए श्री गोयल ने कहा कि यह थीम अनिश्चितताओं, चुनौतियों और काफी उथल–पुथल वाली दुनिया में बहुत प्रासंगिक है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुनिया भर में मची उथल–पुथल के बीच भी भारत अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहा। उन्होंने कहा, ष्आलोचक जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन 7.8ः की विकास दर एक सच्चाई है।ष

अलग–अलग क्षेत्रों में हो वृद्धि का उल्लेख करते हुए श्री गोयल ने बताया कि एसीएमए तेजी से दहाई अंकों की दर से बढ़ रहा था और वाहन क्षेत्र भी तेजी से दहाई अंकों की दर से बढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि इस साल 50 लाख यात्री कारें कारें बिकने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कारें खघ्रीदी जा रही थीं, न कि सिर्फ स्टॉक की जा रही थीं। उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भी उल्लेख किया और बताया कि कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए अब छह महीने का वेटिंग पीरियड है।

उन्होंने बताया कि इस्पात क्षेत्र भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और भारत जितना इस्पात निर्यात करता है, उससे ज्यादा आयात कर रहा है क्योंकि घरेलू मांग बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि वाहन कलपुर्जा उद्योग इस मांग को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रहा है।

श्री गोयल ने औद्योगिक क्षमता और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे सरकार के कई कार्यक्रमों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वाहन कलपुर्जा उद्योग को बड़े पैमाने पर उत्पादन करने और स्पेशियलिटी स्टील (विशेष इस्पात) बनाने वाली कंपनियों को भारत में ही जरूरी इस्पात का उत्पादन करने के लिए जो मदद दी गई, उसका सीधा संबंध इसी उद्योग से है।

उन्होंने वाहन कलपुर्जा के लिए टेक्निकल टेक्सटाइल पीएलआई की अहमियत पर भी जोर दिया, क्योंकि इस इंडस्ट्री को टेक्निकल टेक्सटाइल की जरूरत होती है। साथ ही, उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग को दी गई मदद का उद्देश्य वाहन कलपुर्जा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाना है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार नए इंडस्ट्रियल पार्क बना रही है, और 20 स्मार्ट सिटी व इंडस्ट्रियल सिटी पर पहले से ही काम चल रहा है। उन्होंने उद्योग से इन मौकों का फायदा उठाने का आह्वान किया और दूसरे देशों से भी इन पार्कों में अपने एन्क्लेव (खास इलाके) बनाने पर विचार करने को कहा। उन्होंने कहा, ष्हो सकता है कि हम इनमें से एक पार्क को यूएस–भारत पार्टनरशिप के लिए समर्पित करें। हो सकता है कि हम दो, तीन या पांच ऐसे पार्क बनाएं जो सिर्फ वाहन कलपुर्जों के लिए हों। और मैं आपकी जरूरतों के हिसाब से श्प्लग एंड प्लेश इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकता हूं।ष

श्री गोयल ने कहा कि सुधारों और आगे के सुधारों का सिल. सिला उद्योग के सहयोग से ही तेजी से आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा, ष्हमें आपके आइडिया चाहिए। हमें आपके सुझाव चाहिए। हमें आपकी मांगें जाननी हैं। हमें यह जानना है कि आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, आपको क्या परेशानी हो रही है और हम आपकी और कैसे मदद कर सकते हैं।ष उन्होंने कहा, ष्हम लोगों की बात सुनने वाली सरकार हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी बात रखें।ष उन्होंने उद्योग और सरकार के बीच लगातार बातचीत जारी रखने का आह्वान किया।

श्री गोयल ने डेटा सेंटर उद्योग के साथ अपने हालिया तीन घंटे के संवाद का उल्लेख किया, जिसमें बड़े पैमाने पर संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत आने वाली कंपनियां शामिल थीं। उन्होंने कहा कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वसनीय भागीदार हैं जो हर चीज को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में एक–दूसरे का समर्थन कर सकते हैं।

श्री गोयल ने कहा कि स्थिति स्थिर होने पर भारत में जल्द ही जीसीसी और इजराइल एफटीए होगा। उन्होंने कहा कि भारत महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) तक अधिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर के अन्य देशों के साथ एफटीए भी करेगा, जो लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए आवश्यक हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका और भारत एक श्क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिपश (महत्वपूर्ण खनिजों की साझेदारी) में साझेदार के तौर पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका की श्पैक्स सिलिकाश पहल का भी उल्लेख किया, जिसके तहत समान सोच वाले, लोकतांत्रिक, नेक नीयत और निष्पक्ष व्यवहार करने वाले देश मिलकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई भी एक क्षेत्र व्यापार का इस्तेमाल हथियार के तौर पर न कर सके।

श्री गोयल ने कहा कि इन घटनाक्रमों से वाहन कलपुर्जा उद्योग को वैश्विक खिलाड़ी बनने में मदद मिलेगी, क्योंकि यह 500 अरब डॉलर के उद्योग के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है।

अपनी बात खत्म करने से पहले, श्री गोयल ने उद्योग के लिए कुछ खास प्राथमिकताएं बताईं। उन्होंने उद्योग से कहा कि वे स्थानीय कारोबार को वैश्विक कारोबार में बदलें और जिन उत्पादों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में ज्यादा मजबूती की जरूरत है, उनके लिए एक सक्रिय श्इंडिजनाइजेशन प्रोग्रामश (स्वदेशीकरण कार्यक्रम) शुरू करें, ताकि भविष्य में होने वाली अप्रत्याशित और गंभीर घटनाओं (ब्लैक स्वान इवेंट्स) से बचा जा सके और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने उद्योग से कहा कि वे मूल्य श्रृंखला में ऊपर बढ़ें और ऐसे एकीकृत और बहुत ज्यादा मूल्य वाले समाधान दें, जिनम. अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद शामिल हों जिनकी दुनिया भर में आपूर्ति की जा सके।

श्री गोयल ने सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि उद्योग को सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को पूरी तरह से सरकार पर नहीं छोड़ना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वाहन कलपुर्जा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की बड़ी भूमिका होनी चाहिए, जिसमें बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण और ग्राहकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शामिल है। उन्होंने कस्टमाइज्ड गाड़ियों का भी उल्लेख किया, जो अमेरिका और यूरोप में तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं और बेहतर सुरक्षा सुविधाओं की जरूरत पर जोर दिया।

गाड़ियों को स्क्रैप करने के मामले में श्री गोयल ने कहा कि उद्योग और सरकार को मिलकर पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को नई गाड़ियां खरी. दने वालों के लिए फायदेमंद और काम का सौदा बनाना होगा।

उन्होंने जोर दिया कि यह लक्ष्य सरकार और निजी क्षेत्र की मिली–जुली कोशिशों से ही हासिल किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने अपनी तरफ से वैल्यू और प्रोत्साहन देने की कोशिश की है और उद्योग से अपील की है कि वे आगे आएं और गाड़ियां स्क्रैप होने पर उनकी सही कीमत दें, ताकि नई तरह की गाड़ियों के लिए एक बड़ा बाजार बन सके।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत में अमेरिकी राजदूत माननीय सर्जियो गोर ने ऑटोमोटिव क्षेत्र में बढ़ते अमे. रिका–भारत सहयोग पर प्रकाश डाला और कहा कि यह संबंध ष्ऐतिहासिक उच्च बिंदुष पर है। उन्होंने कहा कि दोनों देश ष्एक साथ मोबिलिटी के भविष्य को मिलकर आकार दे रहे हैं।ष उन्होंने अमेरिका का आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन को मजबूत करने में भारत के वाहन कलपुर्जा उद्योग को एक विश्वसनीय और तेजी से परिष्कृ त भागीदार के रूप में उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारें निष्पक्ष, पारस्परिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार संबंधों की दिशा में काम कर रही हैं और दोनों सरकारों के बीच हुई व्यापार समझ सहित हुई प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका जी20 वार्ता की मेजबानी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल महीने के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करेंगे।

मिस्टर गोर ने फार्मास्यूटिकल्स, सैन्य बिक्री और अभ्यास, आईटी, डेटा सेंटर और अंतरिक्ष के क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने श्पैक्स सिलिका डिक्लेरेशनश को नवाचार को बढ़ावा देने वाले नियामकीय तंत्र की दिशा में एक अहम कदम बताया और कहा कि भारत उन शुरुआती देशों में से एक था जिन्हें इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने भारत के ऑटोमोटिव इकोसिस्टम में अमेरिकी कंपनियों और अमेरिका में भारतीय कंपनियों (जैसे भारत फोर्ज, सुंदरम क्लेटन और महिंद्रा) की मौजूदगी का उल्लेख किया। उन्होंने भारतीय वाहन कलपुर्जे बनाने वाली कंपनियों को अमेरिका में ग्रीनफील्ड असेंबली, आरएंड सेंटर और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए निवेश करने के मौकों पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही, उन्होंने बताया कि अमेरिका में 24 अरब डॉलर के नए निवेश के साथ, भारत में स्थित अमे. रिकी दूतावास दुनिया भर के अमेरिकी दूतावासों में सबसे आगे रहा।

अपने भाषण में, दक्षिण एशिया के लिए ट्रेड कमिश्नर और पश्चिमी भारत के लिए ब्रिटिश उप उच्चायुक्त हरजिंदर कांग ने भारत–यूके संबंधों के मजबूत होने पर जोर दिया और कहा कि ऑटोमोटिव और भविष्य की मोबिलिटी, यूके की आधुनिक विनिर्माण क्षमताओं के केंद्र में हैं। उन्होंने भारत–यूके विजन 2035, यूके की आधुनिक औद्योगिक रणनीति और भारत–यूके सीईटीए (जो 15 जुलाई 2026 को लागू हुआ) का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि यूके की 99ः और भारत की 90ः टैरिफ लाइनों पर ड्यूटी को जीरो या बहुत कम कर दिया गया है, साथ ही व्यापार और कारोबार को आसान बनाने के लिए कस्टम और बॉर्डर प्रक्रियाओं को भी सरल बनाया गया है।

उन्होंने कहा कि सीईटीए आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगा और संयुक्त उपक्रम व साझेदारी को बढ़ावा देगा, जिससे वाहन कलपुर्जा बनाने वाली कंपनियां एक–दूसरे के बाजार में बिना टैरिफ के अपने उत्पाद बेच पाएंगी। उन्होंने आधुनिक इंजीनियरिंग, नवाचार और शून्य उत्सर्जन वाहन प्रौद्योगिकी (जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी, हाइड्रोजन समाधान, हल्के कंपोजिट और सॉफ्टवेयर–आधारित वाहन प्रणाली) के क्षेत्र में यूके की मजबूती पर भी प्रकाश डाला।

नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने पट्टे पर विमान लेने और भुगतान के लिए धन की व्यवस्था करने संबंधी उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता की

नई दिल्ली। पट्टे पर विमान लेने और भुगतान के लिए धन की व्यवस्था करने संबंधी उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की पहली बैठक केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। समिति ने देश के विमानन क्षेत्र के तेजी से विस्तार के अनुरूप भारत में एक मजबूत और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विमान पट्टे पर लेने एवं भुगतान के लिए धन की व्यवस्था करने का तंत्र विकसित करने के उपायों पर विचार–विमर्श किया।

बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव श्री समीर कुमार सिन्हाय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अपर सचिव श्री पुनीत कंसलय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीय वित्त मंत्रालय, वाणिज्य विभागय नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए)य भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के वरिष्ठ अधिकारी तथा उद्योग संघों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

विचार–विमर्श की शुरूआत करते हुए केन्द्रीय मंत्री श्री राम मोहन नायडू ने कहा, "पिछले वर्ष हमने गिफ्ट सिटी में पहला विमान लीजिंग शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। हितधारकों की ओर से दिए गए प्रमुख सुझावों में से एक केप टाउन समझौते की पुष्टि करना था, जिसे हमने विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण कानून लागू करके पूरा किया। इस वर्ष दूसरे विमान लीजिंग शिखर सम्मेलन में उद्योग जगत की ओर से मुझे प्राप्त सुझावों में से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करना था। मुझे खुशी है कि आज हम इसकी पहली बैठक आयोजित कर रहे हैं।"

नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि विमान लीजिंग एक स्थापित और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य व्यवसाय है तथा उपयुक्त कानूनी और नियामकीय उपायों के माध्यम से इस क्षेत्र से जुड़े जोखिमों का क्रमिक रूप से समाधान किया जा रहा है। उन्होंने विमानन क्षेत्र के लिए बैंक ऋण के अधिक आवंटन की संभावनाएं तलाशने तथा विमान लीजिंग में तकनीकी और कौशल विकास के लिए संयुक्त उपक्रमों की पहचान करने का भी सुझाव दिया।

विमान लीजिंग को प्रोत्साहित करने और लीजदाताओं का विश्वास बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। आईएफएससी के माध्यम से 422 परिसंपत्तियों, जिनमें 250 विमान और 87 इंजन शामिल हैं, को लीज पर दिया गया है तथा 474 लीजिंग समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

विमान लीजिंग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का विमानन क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हो रहा है और हर 45 दिन में एक हवाई अड्डा काम करना शुरू कर रहा है, लेकिन विमानों की उपलब्धता अभी भी एक प्रमुख बाधा बनी हुई है। भारतीय विमानन कंपनियों के बेड़े में 85 प्रतिशत से अधिक विमान पट्टे पर लिए गए हैं, इसलिए उन्होंने लीजिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए हितधारकों के साथ निरंतर संवाद के महत्व पर जोर दिया।

समिति ने पट्टे पर विमान लेने और वित्तपोषण के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने से जुड़े कई मुद्दों पर भी विचार–विमर्श किया। इनमें कराधान, नियामकीय ढांचा, वित्त की उपलब्धता और कारोबार में सुगमता जैसे विषय शामिल थे। चर्चा के दौरान विमानों के लिए रुपये में मूल्यांकित वित्तपोषण की संभावनाओं, जीएएआर (सामान्य एंटी–अवॉइडेंस नियम) की प्रयोज्यता के संबंध में अधिक स्पष्टता तथा आयरलैंड के साथ दोहरे कराधान से बचाव समझौते (डीटीएए) के ढांचे पर पुनर्विचारध्पुनर्वार्ता की संभावना पर भी विचार किया गया।

विचार–विमर्श का समापन करते हुए श्री राम मोहन नायडू ने चिन्हित नियामकीय, वित्तपोषण और कराधान संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए समन्वित और समयबद्ध दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। समिति ने सहमति व्यक्त की कि प्रस्तावित उपायों की संबंधित मंत्रालयों, विभागों और हितधारकों के साथ परामर्श कर समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि भारत में विमान लीजिंग और वित्तपोषण के लिए एक पूर्वानुमेय नीतिगत ढांचा विक. सित किया जा सके।

इन सुधारों में भारत के विमानन परिदृश्य को मौलिक रूप से बदलने की क्षमता है, जिससे विमानों की खरीद और वित्तपोषण अधिक आसान, तेज और प्रतिस्पर्धी बन सकेगा। एक पूर्वानुमेय और वैश्विक मानकों के अनुरूप लीजिंग इकोसिस्टम से एयरलाइनों और निवेशकों के लिए कारोबार में सुगमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। वहीं, विमानों की अधिक उपलब्धता से यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी, अधिक विकल्प और यात्रा में सुगमता का लाभ मिलेगा। इससे भारत के एक प्रमुख वैश्विक विमानन केन्द्र के रूप में उभरने की प्रक्रिया को और मजबूती मिलेगी।

पीएम-अजय, अनुसूचित जाति समुदायों के एकीकृत विकास और आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाता है, पीएम-अजय के तहत 'आदर्श ग्राम' के बारे में विस्तृत विवरण िजजचेरूध्ध्चउंहल.हवअ.पदध् पर उपलब्ध है

892 गांवों को 'आदर्श ग्राम' घोषित किया गयाय 2023–24 से 2025–26 के दौरान 1.19 लाख लाभार्थियों को शामिल किया गया आजीविका, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़े उपाय समावेशी विकास को मजबूत करते हैं

नई दिल्ली। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एकीकृत ग्राम विकास, आजी. विका संबंधी अवसरों, कौशल विकास और जरूरी बुनियादी ढांचे के जरिए अनुसूचित जाति समुदायों का सामाजिक–आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से 'प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम–अजय)' को कार्यान्वित कर रहा है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 से, आंध्र प्रदेश में पीएम–अजय के 'आदर्श ग्राम' घटक के तहत कुल 1,159 गांवों का चयन किया गया है। इनमें से 892 गांवों को राज्य सरकार ने 'आदर्श ग्राम' घोषित किया है, जो ग्राम–स्तर पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सामाजिक–आर्थिक नतीजों में उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है।

तिरुपति में चुने गए गांवों की संख्या सबसे अधिक (221) है। इसके बाद प्रकाशम (111), चित्तूर (101), एलुरु (99) और कृष्णा (88) का स्थान है। कृष्णा में चुने गए सभी 88 गांवों को 'आदर्श ग्राम' घोषित किया गया है। श्री सत्य साईं और विजयनगरम में चुने गए सभी गांवों को भी 'आदर्श ग्राम' का दर्जा हासिल हुआ है।

यह योजना अनुसूचित जाति बहुल गांवों में सामाजिक–आर्थिक असमानताओं को कम करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाती है। इसके मुख्य घटकों में पात्र गांवों को 'आदर्श ग्राम' के रूप में विक. सित करना, जिला एवं राज्य–स्तरीय सामाजिक–आर्थिक विकास परियोजनाओं के लिए सहायता–अनुदान प्रदान करना और उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रावासों का निर्माण व मरम्मत शामिल है।

एक 'आदर्श ग्राम' से यह उम्मीद की जाती है कि वहां जरूरी भौतिक एवं सामाजिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो और

वह सामाजिक–आर्थिक विकास के निर्धारित पैमानों पर प्रगति दर्शाए। ग्राम स्तर पर हुई प्रगति का आकलन विकास के अहम क्षेत्रों और जरूरी सेवाओं की सुलभता से जुड़े मापने योग्य पैमानों के आधार पर किया जाता है।

वर्तमान में, चुने गए कुल 267 गांव 'आदर्श ग्राम' का दर्जा हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इन गांवों में जहां बुनियादी ढांचे की कमियों को पूरा करने का काम चल रहा है, वहीं सामाजिक–आर्थिक विकास के पैमानों पर 100 में से 70 अंक हासिल करने के प्रयास भी जारी हैं।

पीएम–अजय के सहायता–अनुदान घटक के तहत, वित्तीय वर्ष 2023–24 से 2025–26 के दौरान आंध्र प्रदेश में 1,19,679 लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया। इस सहायता में बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े कामों के तहत 1,11,697 लाभार्थी, आय सृजन एवं आजीविका से जुड़ी गति. विधियों के तहत 6,132 लाभार्थी और कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत 1,850 लाभार्थी शामिल थे।

बुनियादी ढांचे के विकास से सबसे अधिक लोग लाभान्वित हुए। प्रकाशम में 12,571 लाभार्थी थे। इसके बाद एलुरु में 9,747, पलनाडू में 7,099, तिरुपति में 5,897 और काकीनाडा में 5,764 लाभार्थी थे।

आय सृजन वाली गतिविधियों के तहत, प्रकाशम में 389 लाभार्थियों को शामिल किया गया। इसके बाद तिरुपति में 376, एसपीएसआर नेल्लोर में 367, एलुरु में 327 और डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा में 308 लाभार्थी शामिल थे।

रोजगार की क्षमता बढ़ाने और आजीविका के टिकाऊ अवसरों तक पहुंच आसान बनाने हेतु विभिन्न जिलों में कौशल विकास कार्यक्रम लागू किए गए। एनटीआर और तिरुपति मेंसे प्रत्येक में 160 लाभार्थियों को शामिल किया गया। जबकि पूर्वी गोदावरी, गुंटूर और एसपीएसआर नेल्लोर मेंसे प्रत्येक में 130 लाभार्थियों को शामिल किया गया।

आदर्श ग्राम घटक, जरूरतों पर आधारित ग्राम विकास योजनाओं के जरिए एकीकृत विकास को बढ़ावा देता है। ये योजनाएं बुनियादी ढांचे एवं सेवाओं की आपूर्ति में मौजूद कमियों की पहचान और केन्द्र व राज्य सरकारों की संबंधित योजनाओं के साथ तालमेल बिठाने में मदद करती हैं।

पीएम–अजय के तहत कमी को पूरा करने वाली सहायता का उद्देश्य उन अहम जरूरतों को पूरा करना है जिन्हें मौजूदा कार्यक्रमों द्वारा समग्र रूप से पूरा नहीं किया जा सकता। यह दृष्टिकोण चुने हुए गांवों को बुनियादी सेवाओं को सुदृढ़ करने और मुख्य सामाजिक–आर्थिक पैमानों पर मापने योग्य प्रगति हासिल करने में समर्थ बनाता है।

सहायता–अनुदान वाला घटक आजीविका सृजन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में सहायता प्रदान करके ग्राम स्तर पर विकास को बढ़ावा देता है, जिनसे अनुसूचित जाति समुदायों को सीधे लाभ होता है।

आंध्र प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2023–24 से 2025–26 के दौरान 'आदर्श ग्राम' योजना के तहत कोई अतिरिक्त फंड जारी नहीं किया जा सका, क्योंकि पहले जारी फंड का कुछ हिस्सा खर्च नहीं हुआ था और उपयोग प्रमाण–पत्र लंबित थे। आगे फंड जारी करना इस बात पर निर्भर करेगा कि पहले जारी फंड का कितना उपयोग हुआ है और जरूरी दस्तावेज जमा किए गए हैं या नहीं।

पीएम–अजय के जरिए, सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, आर्थिक अवसरों का विस्तार करने और अनुसू. चत जाति समुदायों के समावेशी व टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

Created by Universal Document Converter

पीडीडी की लापरवाही से सीमावर्ती किसान बेहाल, भारत प्रिये ने आंदोलन की चेतावनी दी

ट्रांसफार्मर बहाल करने में 18 माह की देरी पर भड़के भारत प्रिये, मीरपुर कोना में बिजली बहाली के लिए पीडीडी कोदिया 48 घंटे का अल्टीमेटम

जम्मू। जम्मू–कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेकेपीसीसी) किसान कांग्रेस ने आज परगवाल सेक्टर के सीमावर्ती गांव मीरपुर कोना में बिजली विकास विभाग (पीडीडी) के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। किसान कांग्रेस ने विभाग पर सीमावर्ती क्षेत्र के किसानों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए तत्काल बिजली व्यवस्था बहाल करने की मांग की।

प्रदर्शन का नेतृत्व जेकेपीसीसी किसान कांग्रेस के चेयरमैन भारत प्रिये ने किया। उन्होंने बाढ़ के दौरान करीब डेढ़ वर्ष पहले क्षतिग्रस्त हुए बिजली ट्रांसफार्मर को अब तक दोबारा स्थापित नहीं किए जाने पर पीडीडी की कार्यप्रणाली पर कड़ा रोष जताया। भारत प्रिये ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि करीब 18 माह बीत जाने के बावजूद विभाग क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर को बदलने या दोबारा स्थापित करने में विफल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि खराब ट्रांसफार्मर आज भी खेतों में लावारिस पड़ा हुआ है, जबकि संबंधित विभाग के अधिकारी इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे है।

उन्होंने कहा कि यह स्थिति किसानों के प्रति विभाग की जवाबदेही और संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करती है, खासकर ऐसे सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां किसान पहले ही अनेक कठिनाइयों के बीच खेती कर रहे हैं। भारत प्रिये ने कहा, "क्या सरकार इसी तरह किसानों की मदद करना चाहती है? डेढ़ वर्ष पहले क्षतिग्रस्त हुआ ट्रांसफार्मर आज भी खेतों में पड़ा है और अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। किसानों को सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है।"

उन्होंने कहा कि मीरपुर कोना तथा आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसान धान की खेती के लिए सिंचाई पर निर्भर हैं, लेकिन बिजली की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण कृषि कार्य लगातार महंगे और मुश्किल होते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसान अपनी धान की फसल को बचाने के लिए कर्ज लेकर अथवा उधार पैसे की व्यवस्था कर डीजल इंजन सेट चलाने को मजबूर है। हालांकि, लगातार डीजल इंजन से सिंचाई करना छोटे और सीमांत किसानों के लिए बेहद महंगा साबित हो रहा है और इससे उनकी आर्थिक परेशानियां और बढ़ रही हैं।

भारत प्रिये ने पीडीडी पर "किसान विरोधी रवैया" अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र और किसानों के हित में बड़े–बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसान बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा,

"सरकार खुद को किसान हितैषी नहीं कह सकती, जब किसान पीडीडी की नाकामी की कीमत अपनी जेब से चुका रहे हैं और 18 माह बाद भी एक ट्रांसफार्मर स्थापित नहीं किया जा सका है।"

भारत प्रिये ने संबंधित अधिकारियों से क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर को खेतों से तत्काल हटाकर नया और कार्यशील ट्रांसफार्मर स्थापित करने की मांग की। उन्होंने इतने लंबे समय तक समस्या का समाधान नहीं होने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की भी मांग की।

उन्होंने स्पष्ट किया कि किसान कांग्रेस इस मुद्दे को केवल आश्वासनों के भरोसे दबने नहीं देगी। भारत प्रिये ने पीडीडी को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए प्रभावित किसानों के लिए बिजली ढांचा बहाल करने और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दो दिनों के भीतर पीडीडी ने ठोस कार्रवाई नहीं की तो जेकेपीसीसी किसान कांग्रेस अपना आंदोलन तेज करेगी और विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। "किसान काफी समय से इंतजार कर चुके है। प्रशासनिक लापरवाही के कारण उन्हें अनिश्चितकाल तक परेशान नहीं होने दिया जा सकता। यदि पीडीडी ने 48 घंटे में कार्रवाई नहीं की तो किसान कांग्रेस आंदोलन को और व्यापक करेगी," उन्होंने चेतावनी दी। भारत प्रिये ने जिला प्रशासन और पीडीडी के वरिष्ठ अधिकारियों से मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर प्राथमिकता के आधार पर समस्या का समाधान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के किसान कठिन परिस्थितियों के बावजूद स्थानीय अर्थव्यवस्था और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और उन्हें बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखना उचित नहीं है।

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि विभाग ने समस्या की अनदेखी जारी रखी तो किसान कांग्रेस प्रभावित किसानों को लामबंद करते हुए आंदोलन को और व्यापक रूप देगी। प्रदर्शन में काली मनहास, कुलबीर सिंह, मिलखी मनहास, रतन सिंह, जगतार सिंह, पनू, शिंदा पंच, सिकंदर सिंह और पस्थी सिंह सहित बड़ी संख्या में स्थानीय किसान एवं ग्रामीण शामिल हुए।

रघुनाथ मंदिर में खुले वैष्णो देवी यात्रा पंजीकरण काउंटरः शिवसेना

जम्मू का व्यापार और रोजगार बचाओ, हस्ताक्षर अभियान जारी

जम्मू। शिवसेना (यूबीटी) जम्मू–कश्मीर का 'जम्मू का व्यापार और रोजगार बचाओ जम्मू तवी को प्रमुख रेल टर्मिनल बनाओ' हस्ताक्षर अभियान करण मार्केट से पुरानी मंडी में जारी रहा। अभियान के दौरान दुकानदारों ने रघुनाथ मंदिर में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पंजीकरण काउंटर खोलने की मांग शिवसेना नेताओं के समक्ष रखी।

प्रदेश प्रमुख मनीश साहनी ने कहा कि दुकानदारों की इस मांग को पार्टी प्रमुखता से उठाएगी। उन्होंने कहा कि रघुनाथ मंदिर में पंजीकरण सुविधा मिलने से श्रद्धालु जम्मू में रुककर मंदिर के दर्शन करने के साथ स्थानीय बाजारों, होटलों, टैक्सियों और अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे, जिससे जम्मू के व्यापार और रोजगार को सीधा फायदा मिलेगा।

साहनी ने बताया कि बहुत जल्द जम्मू–कश्मीर के उपराज्यपाल, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी है, तथा श्राइन बोर्ड के ब्ल्ट को

ज्ञापन सौंपकर रघुनाथ मंदिर में पंजीकरण काउंटर खोलने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि माता वैष्णो देवी यात्रा का आर्थिक लाभ केवल कटरा तक सीमित नहीं रहना चाहिए और जम्मू को भी इसका प्रमुख लाभ मिलना चाहिए।

साहनी ने जम्मू तवी रेलवे स्टेशन को लंबी दूरी की ट्रेनों का प्रमुख एवं अंतिम टर्मिनल बनाने तथा जम्मू से कटरा, श्रीनगर सहित प्रमुख गंतव्यों के लिए नियमित कनेक्टिंग ट्रेनें चलाने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा, "जम्मू में सिर्फ ट्रेनें रोकना काफी नहीं, यात्रियों और श्रद्धालुओं को रोकना जरूरी है। जम्मू को केवल ट्रांजिट प्वाइंट नहीं, बल्कि धार्मिक पर्यटन और व्यापार का प्रमुख केंद्र बनाना होगा।"

राजौरी में ट्रैफिक पुलिस का सख्त अभियान, संयुक्त नाकों पर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई

राजौरी (जावेद मन्हास)। सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के उद्देश्य से राजौरी ट्रैफिक पुलिस ने जिले के विभिन्न स्थानों पर विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त नाके स्थापित कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की। इस अभियान की निगरानी स्वयं डीवाईएसपी ट्रैफिक ने मौके पर मौजूद रहकर की। इस दौरान ओवरलोडिंग, बिना वैध दस्तावेज़ वाहन चलाने, सीट बेल्ट एवं हेलमेट का उपयोग न करने, तेज रफ्तार तथा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के चालान किए गए। पैसेंजर वाहनों की भी विशेष जांच की गई ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और क्षमता से अधिक सवारियां ढोने

जैसी अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सके। ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया कि सड़क पर लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ़ आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। डीवाईएसपी ट्रैफिक ने आम जनता और वाहन चालकों से अपील की कि वे यातायात नियमों का पालन करें, सभी ज़रूरी दस्तावेज़ साथ रखें और सुरक्षित व ज़िम्मेदारी के साथ वाहन चलाएं।

Printer, Publisher, Owner, Editor by: Sanktha Prasad Singh Published from: GH Road Skara, Near Ladakh Public School, Leh (Ladakh) - 194104, Published from: Ladakh Imperial Printing press, Gh Skara, Near Ladakh Public School, Leh Ladakh, 194104, Mob.: Mob.: 9818069272, 8287390112, Email: ladakhtoday@gmail.com
**All disputes are subject to the exclusive jurisdiction of competent courts and forums in Leh - city.

Created by Universal Document Converter